vishikhamedia@gmail.com

विभिन्न विषयों पर आधारित राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

RNI No. UTTHIN/2021/80704

मूल्य:35 रुपये

तीर निशाने पर

विशिखा

वर्ष:05 अंक:7 जुलाई 2025 पृष्ठ:32

उत्तराखण्ड संस्करण

_vishikhamedia/
vishikhamedia/
vishikhamedia/
vishikhamedia
vishikhamedia.in

सावन मास : शिवभक्तों की आस्था की प्रतीक कांवड़ यात्रा

कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने कसी कमर। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की।

विशिखा

विशिखा न्यूज़ 24x7

आपकी बात, आपके साथ

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

तीर निशाने पर

विशिखा

अब डिजिटल एडिशन में भी उपलब्ध

www.vishikhamedia.in

अंदर

२१ जून योग दिवस 10

प्राचीन परंपराओं को समेटे आधुनिक युग का योगा

08 | केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार के प्रयासों को सराहा

08 | देश में ऑनलाइन लूडो के बढ़ते खतरे पर कैसे लगेगी लगाम?

14 | संविधान में समाजवाद-धर्मनिरपेक्षता की एंट्रीः इंदिरा की विरासत या साजिश

16 | सुविधा और दुविधा में फंसी यूपी के बेसिक शिक्षकों की तबादला नीति

18 | प्रयागराज में दलित बच्चियों का धर्म बदलकर आतंकवादी बनाने की साजिश का बड़ा खुलासा

20 | अमित शाह ने मौर्य को 'मेरे मित्र' पुकारा तो छिड़ गई सियासी चर्चा

22 | प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की बातचीत विदेश नीति की परिपक्वता की मिसाल

24 | मोदी का हनुमान अब खुद बनना चाहता है बिहार का राम

26 | सरकार ने अ नलाइन स्कैम पर कसा शिकंजा-चार मोर्चों पर लिया एक्शन

16 | इस युद्ध का भविष्य अनिश्चित है, इसके परिणाम पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगे

30 | पेशाब से मीठी या फल जैसी गंध को न करें नजरअंदाज' हो सकता है ब्लड शुगर बढ़ने का संकेत

विशिखा
तीर निशाने पर
अंक: 7 वर्ष: 06, जुलाई 2025

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
प्रियल श्रीवास्तव
सम्पादक
अनिल कुमार श्रीवास्तव
डिजाइन
देवेन्द्र नेगी, उत्तराखण्ड

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक **अनिल कुमार श्रीवास्तव** द्वारा **भास्कर प्रिंटिंग प्रेस, डी.बी. कॉर्प लिमिटेड** शिवदासपुरा, टोंक रोड, जयपुर से छपवाकर एवं **विशिखा मीडिया** सी-29, शिवलोक कॉलोनी, लाडपुर-राजपुर रोड, देहरादून 248008 उत्तराखण्ड से प्रकाशित

पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका में प्रकाशित सामग्री के विषय में अपनी प्रतिक्रियाएं एवं सुझाव अवश्य भेजें। अपनी प्रतिक्रियाएं एवं सुझावों को आप हमें vishikhamedia@gmail.com पर ई-मेल भी कर सकते हैं।
लेखकों से निवेदन है कि कृपया अपनी स्व-लिखित एवं मौलिक रचनायें ही भेजें। रचनाओं के साथ अपना पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल एवं फोटो अवश्य भेजें। रचनाओं के छापने या न छापने का अधिकार संपादकीय मंडल का होगा। अस्वीकृत रचनायें लौटाई नहीं जाएंगी।
पत्रिका में प्रकाशित सभी लेख एवं रचनाओं में संपादक की सहमति हो, यह आवश्यक नहीं है। पत्रिका में प्रकाशित आलेख एवं रचनायें लेखकों के निजी विचार हैं। प्रकाशित सामग्री के उपयोग करने से पूर्व में संपादक की लिखित सहमति आवश्यक है।
'किसी भी तरह के विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर (राजस्थान) होगा।
'पत्रिका में प्रकाशित कुछ चित्र, लेख एवं आंकड़े को इन्टरनेट एवं अन्य वेबसाइट से लिया गया है।

विशिखा न्यूज़ 24x7
आपकी बात, आपके साथ

सम्पादक की कलम से

अनिल कुमार श्रीवास्तव

योग शब्द का अर्थ एक्य या एकतत्व होता है, जो संस्कृत धातु उसे से निर्मित है जिसका शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है की "योग कर्मसु कौशल्यम " यानी यानी योग से कर्मो में कुशलता आती है। व्यावहारिक स्तर पर योग शरीर मन और भावनाओं में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने का एक साधन है। योग का इतिहास बहुत पुराना है और इसकी शुरुआत के बारे में निश्चित रूप से कह पाना कठिन है।

योग का उद्गम भारत में हुआ था, लेकिन यह बड़ी तेजी से पूरे विश्व में विख्यात हो गया है और योग का महत्व आजकल की दुनिया में बढ़ गया है। योग का विकास महर्षि पतंजलि के 'योग सूत्र' के साथ जुड़ा है, जिन्होंने इसे सिद्ध किया और योग के अंगों को प्रस्तुत किया। इसमें योग के आठ प्रमुख अंगों को विवरणित किया था, जिनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और समाधि शामिल थे। योग का उद्देश्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, आत्मा के विकास, और आत्मा का परमात्मा के साथ मिलान है। भारतीय धर्म और दर्शन में योग का अत्यधिक महत्व है। जैन और बौद्ध दर्शनों में भी योग के महत्व को स्वीकृति प्राप्त है। योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है तथा विचार संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है जिससे स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की प्राप्ति होती है। योग हमारी बदलती जीवन शैली में चेतना बनाकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है।

शेष फिर....

उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 रुद्रपुर

उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 में केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार के प्रयासों को सराहा

धामी सरकार पारदर्शिता, तीव्रता और दूरदर्शिता के साथ कर रही काम

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को उत्तराखंड के रुद्रपुर में आयोजित उत्तराखंड निवेश उत्सव–2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के प्रयासों की जमकर सराहना की। दिसंबर 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद एक लाख करोड़ रुपए के निवेश की सफल ग्राउंडिंग का उत्सव मनाते हुए शाह ने कहा कि धामी सरकार पारदर्शिता, तीव्रता और दूरदर्शिता के साथ काम कर रही है। उन्होंने जोर दिया कि विकसित उत्तराखंड के बिना 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता।

गृह मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि देवभूमि उत्तराखंड ने पूरी दुनिया को आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। उन्होंने दिसंबर 2023 की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जिक्र करते हुए कहा, "तब मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कहा था कि असल पराक्रम समिट में हुए तीन लाख 56 हजार करोड़ के एमओयू को धरातल पर उतारने का होगा।

मुझे खुशी है कि धामी की टीम ने तमाम चुनौतियों के बावजूद आज एक लाख करोड़ का निवेश धरातल पर उतार दिया है।" उन्होंने बताया कि इस निवेश से 81 हजार नए रोजगार सृजित हुए हैं, और सहायक उद्योगों के जरिए भी ढाई लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

शाह ने इस बात पर जोर दिया कि उत्तराखंड के दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में भी अब उद्योग लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करते हुए, नीति में पारदर्शिता, क्रियान्वयन में तीव्रता और विजन में दूरदर्शिता के साथ विकास का नया खाका खींचने में सफल रही है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री

अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा उत्तराखंड के गठन और केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से लगातार चल रही 'डबल इंजन' सरकार के लाभों का भी उल्लेख किया।

केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से चौथे नंबर पर आ गई है, और 2027 तक इसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा, "मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत की कल्पना की है, लेकिन विकसित उत्तराखंड के बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं है।"

शाह ने गरीबों के कल्याण और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में मोदी सरकार की उपलब्धियों का भी संक्षिप्त उल्लेख किया, जिसमें 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना शामिल है। उन्होंने जोर दिया कि देश के समग्र विकास के लिए छोटे राज्यों और पूर्वोत्तर के राज्यों का विकास भी महत्वपूर्ण है, जिस पर केंद्र सरकार विशेष ध्यान दे रही है।

उत्तराखण्ड को औद्योगिक विकास की ऊंचाइयों तक ले जाएगा यह उत्सव - सीएम धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का स्वागत करते हुए कहा कि आज हम उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में एक लाख करोड़ रूपए से अधिक की सफलतापूर्वक ग्राउंडिंग का उत्सव मना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि आज का उत्सव केवल आर्थिक निवेश नहीं, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संभावनाओं, उद्यमिता की भावना और जन भागीदारी पर आधारित समावेशी विकास का प्रतिबिंब है, जो राज्य को आत्मनिर्भरता और औद्योगिक समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आज 1342 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है।

सावन मास : शिवभक्तों की आस्था की प्रतीक कांवड़ यात्रा

कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने कसी कमर

सावन मास के शुरू होते ही शिवभक्तों की आस्था की प्रतीक कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है। यह हमारे देश में धार्मिक आस्था का प्रतीक मानी जाती है। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालु पवित्र नदियों से जल भरकर लंबी दूरी की यात्रा करते हैं और उस जल को शिवलिंग या फिर ज्योतिर्लिंग पर अर्पित करते हैं।

सावन मास के शुरू होते ही शिवभक्तों की आस्था की प्रतीक कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है। यह हमारे देश में धार्मिक आस्था का प्रतीक मानी जाती है। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालु पवित्र नदियों से जल भरकर लंबी दूरी की यात्रा करते हैं और उस जल को शिवलिंग या फिर ज्योतिर्लिंग पर अर्पित करते हैं। सावन माह शुरू होते ही कांवड़िए भारी–भरकम कांवड़ उठाकर गंगाजल लेने के लिए हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री जैसे पवित्र स्थानों पर जाते हैं। इस बार 11 जुलाई 2025 से सावन माह की शुरूआत हो रही है। तो आइए जानते हैं कांवड़ यात्रा की डेट, महत्व और कैसे इस यात्रा की शुरूआत हुई।

कांवड़ यात्रा 2025

इस बार आज यानी की 11 जुलाई 2025 से कांवड़ यात्रा की शुरूआत हो रही है, जोकि सावन माह का पहला दिन है। 23 जुलाई 2025 को यह यात्रा सावन शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक के साथ पूर्ण होगी। इस दौरान देवघर जैसे तीर्थ स्थलों पर पूरे सावन के महीने तक श्रद्धालु जल चढ़ाने के लिए कांवड़ यात्रा करते हैं।

ऐसे शुरू हुई थी कांवड़ यात्रा

जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तो उसमें से 14 रत्न निकले थे, साथ ही खतरनाक विष भी निकला था। जिसको हलाहल कहा गया है। इस विष के कारण पूरी सृष्टि खतरे में पड़ गई थी। तब भगवान शिव ने उस विष को पीकर अपने कंठ में धारण किया था। इस विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और उनको नीलकंठ कहा जाने लगा। इस विष का असर इतना तेज था कि भगवान शिव के शरीर में जलन होने लगी और उनका असहनीय पीड़ा हुई। इस पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए देवताओं ने भगवान शिव को पवित्र नदियों का ठंडा जल अर्पित करना शुरूकर दिया।

बता दें कि दशानन रावण भगवान शिव का पहला कांवड़िया था, वह कांवड़ में गंगाजल में भरकर लाए थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास महादेव मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। इससे भगवान शंकर को विष की पीड़ा से राहत मिली थी।

कांवड़ यात्रा का महत्व

कांवड़ यात्रा करने से भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं और वह अपने भक्तों को भय, रोग, शोक और दरिद्रता से मुक्त करते हैं। गंगाजल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करना बेहद पुण्यकारी माना जाता है। इस यात्रा को करने से जातक

के पापों का नाश होता है और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। वहीं सावन महीना भी भगवान शिव को अतिप्रिय होता है, इस महीने भगवान शिव की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है।

कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने कसी कमर

उधर कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कांवड़ यात्रा, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन और कानून व्यवस्था से जुड़े हुए विषयों पर बातचीत की गई।

साथ ही कांवड यात्रा के मार्गों में सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाओं पर भी चर्चा हुई। ऐसे में उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज गति से चल रही है।

कांवड़ यात्रा पथ पर ढाबों पर फिलहाल लगाना ही होगा क्यूआर कोड, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी-उत्तराखंड सरकार से जवाब तो मांगा, लेकिन रोक नहीं लगाई

यूपी सरकार के वकील जितेंद्र कुमार सेठी ने कहा कि मामला संगीन है और हमें दो हफ्ते का वक्त चाहिए। जिसके बाद इस मामले में 22 तारीख की सुनवाई की वक्त मुकर्रर कर दी। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और शिक्षाविद् अपूर्वानंद झा एवं अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 22 जुलाई के लिए स्थगित कर दी।

सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार की बड़ी जीत हुई है। क्यूआर कोड मामले को लेकर याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल की थी, उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 2 मिनट की सुनवाई हुई। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और 23 तारीख तक खत्म हो जाना है। लेकिन याचिकाकर्ता को इस मामले में अंतरिम राहत की उम्मीद थी। लेकिन सुनवाई की शुरुआत के समय ही उत्तराखंड सरकार और यूपी सरकार के वकील जितेंद्र कुमार सेठी ने कहा कि मामला संगीन है और हमें दो हफ्ते का वक्त चाहिए। जिसके बाद इस मामले में 22 तारीख की सुनवाई की वक्त मुकर्रर कर दी। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और शिक्षाविद् अपूर्वानंद झा एवं अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 22 जुलाई के लिए स्थगित कर दी।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश द्वारा जारी इसी तरह के निर्देशों पर रोक लगा दी थी, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित भोजनालयों को अपने मालिकों, कर्मचारियों के नाम और अन्य

विवरण प्रदर्शित करने के लिए कहा गया था। 25 जून को उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति का हवाला देते हुए झा ने कहा कि नए उपायों में कांवड़ मार्ग पर सभी भोजनालयों पर क्यूआर कोड प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है, जिससे मालिकों के नाम और पहचान का पता चलता है, जिससे वही भेदभावपूर्ण प्रोफाइलिंग प्राप्त होती है जिस पर पहले इस न्यायालय ने रोक लगा दी थी।

याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार का निर्देश, जिसमें स्टॉल मालिकों को कानूनी लाइसेंस आवश्यकताओं के तहत धार्मिक और जातिगत पहचान बताने के लिए कहा गया है, दुकान, ढाबा और रेस्टोरेंट मालिकों के निजता के अधिकार का उल्लंघन है। हिंदू कैलेंडर के श्रावणश माह में शिवलिंगों का श्जलाभिषेकश करने के लिए कई भक्त गंगा से पवित्र जल लेकर विभिन्न स्थानों से कांवड़ लेकर आते हैं। कई श्रद्धालु इस महीने में मांसाहार से परहेज करते हैं। कई लोग तो प्याज और लहसुन वाला भोजन भी नहीं खाते।

देश में ऑनलाइन लूडो के बढ़ते खतरे पर कैसे लगेगी लगाम?

अजय कुमार
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ

रमेश, एक मध्यमवर्गीय परिवार का साधारण युवक था। शहर के एक निजी कंपनी में मामूली वेतन पर काम करता और अपने छोटे से परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। उसकी दिनचर्या काम से घर और कभी–कभार दोस्तों के साथ चाय पीने तक ही सीमित थी। लेकिन कुछ महीने पहले, उसके एक सहकर्मी ने उसे ऑनलाइन लूडो के एक ऐप के बारे में बताया। शुरुआत में रमेश ने इसे सिर्फ मनोरंजन का एक साधन समझा। काम से लौटने के बाद या खाली समय में वह दोस्तों या अनजान लोगों के साथ लूडो खेलता, और कभी–कभार छोटी–मोटी बाजी भी लगा लेता।

शुरुआत में सब कुछ रोमांचक और मजेदार लग रहा था। जीत की खुशी और हार का मामूली गम, यह सब उसकी नीरस जिंदगी में एक नया रंग भर रहा था। धीरे–धीरे, रमेश इस खेल का आदी होता चला गया। अब वह काम के दौरान भी चोरी–छिपे लूडो खेलने लगा था, और घर पर परिवार को कम समय देता था। उसकी पत्नी अक्सर शिकायत करती कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा, हमेशा फोन में ही घुसा रहता है। रमेश इन बातों को अनसुना कर देता, उसे तो बस अगली बाजी जीतने की धुन सवार रहती थी।

एक दिन, रमेश ने एक बड़े दांव पर अपनी महीने भर की कमाई लगा दी। उसे पूरा भरोसा था कि वह जीत जाएगा, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वह बुरी तरह हार गया। इस हार ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब वह घर कैसे चलाएगा और अपनी पत्नी को क्या जवाब देगा। रातों की नींद उड़ गई, और वह हर समय उदास और चिड़चिड़ा रहने लगा। भारत में ऑनलाइन लूडो का चलन तेजी से बढ़ रहा है, खासकर युवाओं और कम आय वर्ग के लोगों के बीच। इसकी आसान उपलब्धता और कम समय में ज्यादा पैसे कमाने के लालच ने लाखों लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। यह सिर्फ एक खेल नहीं रह गया है, बल्कि एक तरह का नशा बन गया है जो लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है।

यह खेल इतना आकर्षक और आसान है कि लोग आसानी से इसके आदी हो जाते हैं। लगातार खेलने की इच्छा और हर बार जीतने की उम्मीद उन्हें घंटों तक स्क्रीन से चिपके रहने पर मजबूर कर देती है, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। नींद की कमी, आंखों में दर्द, तनाव और चिंता जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। दूसरा बड़ा खतरा है वित्तीय नुकसान। ऑनलाइन लूडो में अक्सर पैसे की बाजी लगाई जाती है। जीतने का लालच लोगों को अपनी जमा पूंजी और यहां तक कि कर्ज लेकर भी दांव लगाने के लिए प्रेरित करता है। हारने पर उन्हें भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है।

कई मामले ऐसे सामने आए हैं जहां लोगों ने कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या तक कर ली है। तीसरा खतरा है सामाजिक अलगाव।कुछ ऐप गैरकानूनी तरीके से काम करते हैं और खिलाड़ियों से पैसे ऐंठ लेते हैं। इसके अलावा, कुछ खिलाड़ी हैकिंग या अन्य गलत तरीकों का इस्तेमाल करके दूसरों को हराते हैं, जिससे ईमानदार खिलाड़ियों को नुकसान होता है।

अब सवाल यह उठता है कि इस ऑनलाइन लूडो के बढ़ते खतरे पर लगाम कैसे लगाई जाए? इसके लिए कई स्तरों पर काम करने की जरूरत है। सबसे पहले लोगों को ऑनलाइन लूडो के खतरों के बारे में जागरूक करना होगा। इसके लिये सरकार और गैर–सरकारी संगठनों को मिलकर जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में बताना चाहिए। मीडिया भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लोगों को यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि एक गंभीर लत बन सकता है जो उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है।

इसके अलावा ऑनलाइन लूडो प्लेटफॉर्म को कानूनी दायरे में लाना जरूरी है। सरकार को ऐसे नियम और कानून बनाने चाहिए जो इन प्लेटफॉर्म की गतिविधियों को नियंत्रित करें और खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करें। सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए लाइसेंसिंग और विनियमन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि धोखाधड़ी जालसाजी को रोका जा सके। ऑनलाइन लूडो ऐप्स में ऐसे फीचर होने चाहिए जो खिलाड़ियों को अपनी खेलने की सीमा निर्धारित करने और समय–समय पर ब्रेक लेने के लिए प्रोत्साहित करें।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब तनाव, चिंता और बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, ऐसे समय में योग एक ऐसा समाधान बनकर उभरा है जो तन, मन और आत्मा तीनों को संतुलित करता है। भारत की इस प्राचीन परंपरा को आज वैश्विक स्तर पर अपनाया जा रहा है। इसी परंपरा को सम्मान देने और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर वर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है।

योग का अर्थ और महत्व

'योग' शब्द संस्कृत के "युज्" धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कृ 'जुड़ना'। इसका आशय है आत्मा का परमात्मा से, शरीर का मन से और व्यक्ति का ब्रह्मांड से जुड़ाव। योग मात्र शारीरिक व्यायाम नहीं है, यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें आसन, प्राणायाम, ध्यान और ध्यानावस्था शामिल होती है।

योग दिवस की शुरुआत

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की नींव 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखी थी। उन्होंने कहा था–

"योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। यह शरीर और मन, क्रिया और विचार, संयम और पूर्ति की एकता का प्रतीक है।"

भारत के इस प्रस्ताव को 193 में से 177 देशों ने समर्थन दिया। इस प्रकार 21 जून को हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को पूरे विश्व में बड़े उत्साह से मनाया गया। भारत में राजपथ, नई दिल्ली में हुए आयोजन में करीब 35,000 लोगों ने भाग लिया और एक नया विश्व रिकॉर्ड बना।

योग दिवस 21 जून को ही क्यों?

21 जून को ग्रीष्म संक्रांति होती है, यानी वर्ष का सबसे लंबा दिन। यह प्रकृति और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन का प्रतीक है। यही कारण है कि इस दिन को योग दिवस के लिए चुना गया।

योग के प्रकार

- **हठ योगः** शारीरिक आसनों पर आधारित योग प्रणाली।
- **राज योगः** मानसिक और आत्मिक विकास पर केंद्रित।
- **कर्म योगः** निःस्वार्थ सेवा और कार्य के माध्यम से आत्मविकास।
- **भक्ति योगः** ईश्वर भक्ति के माध्यम से आत्मा का विकास।
- **ज्ञान योगः** तर्क, विवेक और ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति।

योग के लाभ

शारीरिक लाभ

- लचीलापन बढ़ाता है
- रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है
- हृदय, फेफड़े और पाचन क्रिया सुधरती है

मानसिक लाभ

- तनाव, अवसाद और चिंता से राहत
- आत्मविश्वास में वृद्धि
- स्मरण शक्ति और एकाग्रता बेहतर होती है

आध्यात्मिक लाभ

- आंतरिक शांति की अनुभूति
- ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान
- प्रकृति से जुड़ाव

आज के परिप्रेक्ष्य में योग की प्रासंगिकता आज के समय में जब पूरी दुनिया मानसिक तनाव, खराब जीवनशैली और अनेक बीमारियों से जूझ रही है, योग न केवल एक व्यायाम बल्कि एक जीवन दर्शन बनकर सामने आया है। स्कूलों, दफ्तरों, जेलों, अस्पतालों में योग अपनाया जा रहा है। यह केवल स्वास्थ्य का साधन नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। अपने जीवन में योग को अपनाना चाहिए ताकि वह स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन जी सके।

इसीलिए कहते हैं कि
योग करें, निरोग रहें।

हर वर्ष की एक अलग थीम

योग दिवस की हर वर्ष एक अलग थीम होती है जो उस वर्ष के वैश्विक मुद्दों से जुड़ी होती है।

वर्ष	थीम
2015	योग से मेल-जोल और शांति
2016	युवाओं को जोड़ने में योग की भूमिका
2017	स्वास्थ्य के लिए योग
2018	शांति के लिए योग
2019	जलवायु कार्यवाही के लिए योग
2020	घर पर योग, परिवार के साथ योग
2021	स्वास्थ्य के लिए योग
2022	मानवता के लिए योग
2023	वसुधैव कुटुम्बकम के लिए योग
2024	योग, प्रकृति और स्वास्थ के लिए एकता
2025	एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग

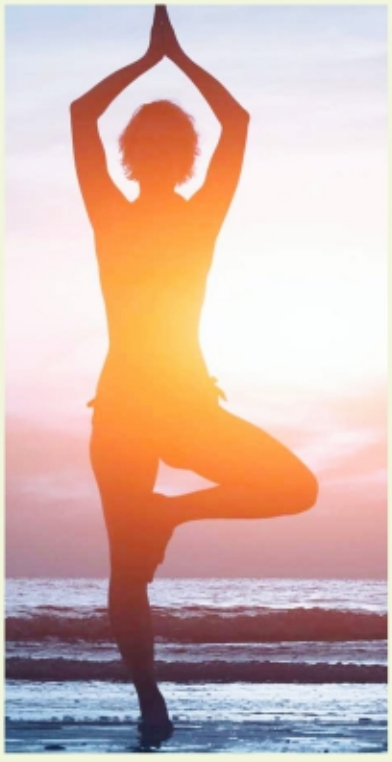

२१ जून योग दिवस

प्राचीन परंपराओं को समेटे आधुनिक युग का योगा

योग दिवस के जनक भारत में भी इस दिन योग की शुरुआत सूरज की पहली किरण के साथ एक अनोखे उत्साह से होती है। सरकारी से लेकर तमाम सामाजिक संगठनों द्वारा पूरे देश में योग के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं

संजय सक्सेना
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ

21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में अपनी लोकप्रियता हासिल करता जा रहा है। 12 वर्ष पहले इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को योग दिवस मनाने का संदेश दिया था, जिसे पूरी दुनिया में सराहा और स्वीकारा गया। योग दिवस के जनक भारत में भी इस दिन योग की शुरुआत सूरज की पहली किरण के साथ एक अनोखे उत्साह से होती है। सरकारी से लेकर तमाम सामाजिक संगठनों द्वारा पूरे देश में योग के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी कैबिनेट के सदस्यों से लेकर राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री, नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बुद्धिजीवी इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। भाग दौड़ की इस जिंदगी में शारीरिक व्यायाम जब पीछे छूटता जा रहा है ऐसे में योग दिवस शरीर को स्वस्थ्य रखने के लिये एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने वाला

यह दिन केवल शारीरिक व्यायाम का प्रतीक नहीं, बल्कि मानव जीवन को संतुलित करने की एक गहरी कला का उत्सव है। बीते वर्ष 21 जून की सुबह की ठंडी हवा में, जब दिल्ली के इंडिया गेट पर हजारों लोग योग के लिए एकत्र हुए, तो वह दृश्य किसी सांस्कृतिक उत्सव से कम नहीं था। रंग–बिरंगे योग मैट, अलग–अलग उम्र के लोग, और एक सामूहिक ऊर्जा ने वातावरण को जीवंत कर दिया। यह केवल एक दिन की बात नहीं थीय यह एक वैश्विक आंदोलन का हिस्सा था, जो भारत की प्राचीन परंपरा को दुनिया के कोने–कोने तक ले गया। इस बार भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलने वाला है।

योग, जो कभी भारतीय ऋषि–मुनियों की तपस्या का हिस्सा था, आज एक वैज्ञानिक और समग्र जीवन शैली के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, फिर भी यह आधुनिक जीवन की जटिलताओं के लिए उतना ही प्रासंगिक है। 21 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने का प्रस्ताव जब भारत ने 2014 में रखा, तो इसे 177 देशों का समर्थन मिला। यह केवल एक राजनयिक जीत नहीं थी, बल्कि मानवता के लिए एक साझा दृष्टिकोण था। योग का अर्थ केवल आसन या शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं हैय यह मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने

की कला है।

इस दिन दिल्ली के अलावा देश के कोने–कोने में और दुनिया के विभिन्न शहरों में लोग योग के लिए एकत्र होते हैं। स्कूलों में बच्चे, कार्यालयों में कर्मचारी, और गांवों में किसान, सभी ने अपने–अपने तरीके से इस दिन को मनाते हैं। गौरतलब हो, योग की यह सार्वभौमिक स्वीकार्यता इसके लचीलेपन और समावेशी स्वभाव को दर्शाती है। एक तरफ जहां युवा सूर्य नमस्कार के गतिशील आसनों में ऊर्जा पाते हैं, वहीं वरिष्ठ नागरिक प्राणायाम और ध्यान में शांति तलाशते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो उम्र, लिंग, या सामाजिक स्थिति की सीमाओं को तोड़ती है, लेकिन योग दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं हैय यह एक गहरे विश्लेषण की मांग करता है। आधुनिक जीवनशैली में तनाव, चिंता, और शारीरिक रोगों की बढ़ती संख्या ने योग को और भी जरूरी बना दिया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं 2030 तक वैश्विक स्वास्थ्य बोझ का एक बड़ा हिस्सा होंगी। योग, विशेष रूप से ध्यान और प्राणायाम, तनाव को कम करने और

योग, जो कभी भारतीय ;षि-मुनियों की तपस्या का हिस्सा था, आज एक वैज्ञानिक और समग्र जीवन शैली के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, फिर भी यह आधुनिक जीवन की जटिलताओं के लिए उतना ही प्रासंगिक है। 21 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने का प्रस्ताव जब भारत ने 2014 में रखा, तो इसे 177 देशों का समर्थन मिला।

मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में प्रभावी साबित हुआ है। वैज्ञानिक अध्ययनों ने दिखाया है कि नियमित योग अभ्यास से कोलेस्ट्रोल जैसे तनाव हार्मोन का स्तर कम होता है, जिससे चिंता और अवसाद में कमी आती है।

हालांकि, योग के प्रचार में कुछ चुनौतियां भी हैं। इसे केवल एक शारीरिक व्यायाम के रूप में प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति ने इसके आध्यात्मिक और दार्शनिक आयामों को धुंधला किया है। पतंजलि के योगसूत्र, जो योग के आठ अंगोंकृयम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और समाधिकृत का वर्णन करते हैं, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। फिर भी, बाजारीकरण और व्यावसायीकरण ने योग को कभी–कभी एक फैशन स्टेटमेंट या फिटनेस ट्रेंड तक सीमित कर दिया है। योग स्टूडियो, महंगे योग मैट, और डिजाइनर योग वस्त्र इसकी मूल सादगी को चुनौती देते हैं।

इसके बावजूद, 21 जून का दिन हमें याद दिलाता रहता है कि योग केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी है। योग हमें अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया के साथ सामंजस्य बिठाने की प्रेरणा देता है। जब लोग एक साथ योग करते हैं, तो एक सामूहिक ऊर्जा पैदा होती है, जो न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि सामुदायिक स्तर पर भी सकारात्मक बदलाव लाती है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि योग केवल एक प्राचीन परंपरा नहीं, बल्कि एक आधुनिक समाधान है, जो हमें एक स्वस्थ, संतुलित, और सार्थक जीवन की ओर ले जाता है।

संविधान की प्रस्तावना

पर संघ का प्रश्न या भारत की आत्मा पर चोट?

अजय कुमार
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ

भारतीय राजनीति में जब भी संविधान को लेकर कोई सवाल उठता है, तब वह बहस सिर्फ कानून की सीमाओं तक सीमित नहीं रहती बल्कि वह देश की आत्मा और उसकी पहचान से जुड़ जाती है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने जो बयान दिया, उसने न केवल संविधान की प्रस्तावना बल्कि स्वतंत्र भारत की विचारधारा को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि संविधान की प्रस्तावना में जो 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द 1976 में इमरजेंसी के दौरान जोड़े गए थे, वे शब्द उस दौर की तानाशाही में बिना जनता की सहमति के थोपे गए थे और अब समय आ गया है कि इन शब्दों को हटाने पर गंभीर विचार किया जाए। उनका यह बयान प्रतीकात्मक नहीं बल्कि एक वैचारिक लड़ाई की ओर संकेत करता है जो अब साफ तौर पर राष्ट्र की पहचान पर केंद्रित हो गई है। जब इमरजेंसी लगाई गई थी तब देश के लोकतांत्रिक संस्थानों को कुचल दिया गया था। प्रेस की आजादी खत्म कर दी गई थी, विपक्षी नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया था और संसद मात्र एक औपचारिकता बन कर रह गई थी। ऐसे समय में जब नागरिकों की आवाज को दबा दिया गया था, तब 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द जोड़े गए थे। यही वह आधार है जिस पर संघ का कहना है कि यह बदलाव लोकतंत्र के विरुद्ध था और इसीलिए अब इन्हें हटाने की आवश्यकता है।

दत्तात्रेय होसबाले के बयान के बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं आईं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि संघ 1949 से ही संविधान का विरोध करता आ रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संघ समर्थकों ने पंडित नेहरू और डॉ. भीमराव आंबेडकर के पुतले तक जलाए थे। वहीं कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने इसे संघ की 'मनुस्मृति आधारित भारत' की सोच का हिस्सा बताया और कहा कि यह प्रयास दरअसल भारत के बहुलतावादी और समावेशी स्वरूप को मिटाने की दिशा में एक कदम है। लेकिन इस पूरे विवाद को केवल राजनीतिक

प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में देखना एक सीमित दृष्टिकोण होगा क्योंकि यह बहस आज की नहीं है, इसका इतिहास उस समय से है जब संविधान सभा में ही इन शब्दों को लेकर मतभेद थे। संविधान सभा के सदस्य प्रोफेसर के. टी. शाह ने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। उनका मानना था कि इन शब्दों से संविधान की दिशा और नीति स्पष्ट होगी। लेकिन डॉ. भीमराव आंबेडकर ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इन शब्दों को संविधान में जोड़ना लोकतंत्र के लचीलेपन को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने तर्क दिया था कि समाजवाद जैसे शब्द किसी एक आर्थिक विचारधारा को बाध्यकारी बना देंगे जबकि लोकतंत्र में नीति तय करने का अधिकार जनता और समय के अनुसार सरकारों के पास होना चाहिए।

डॉ. आंबेडकर ने यह भी स्पष्ट किया था कि समाजवादी मूल्यों की झलक संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में पहले से ही मौजूद है और धर्मनिरपेक्षता की गारंटी मौलिक अधिकारों के माध्यम से दी गई है। इसलिए इन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ना अनावश्यक है। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू ने भी इन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ने की कभी सिफारिश नहीं की थी। उनका मानना था कि भारतीय संविधान का ढांचा ही धर्मनिरपेक्ष और समावेशी है और यह बिना कहे ही सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है। लेकिन 1976 में जब देश इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ दिया। उस समय संसद में विपक्ष लगभग नगण्य था, जन प्रतिनिधित्व निष्क्रिय था और विरोध की आवाजें दबा दी गई थीं। सरकार ने इसे 'कल्याणकारी राज्य' की प्रतिबद्धता बताया लेकिन विपक्ष और अनेक संवैधानिक विशेषज्ञों ने इसे सत्ता के दुरुपयोग का प्रतीक बताया।

हालांकि इमरजेंसी के बाद 1977 में जब जनता पार्टी सत्ता में आई, तब वह चाहे

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि संघ 1949 से ही संविधान का विरोध करता आ रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संघ समर्थकों ने पंडित नेहरू और डॉ. भीमराव आंबेडकर के पुतले तक जलाए थे।

तो इन शब्दों को प्रस्तावना से हटा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यह भी इस बहस का एक दिलचस्प पक्ष है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार केस 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना और कहा कि संविधान संशोधन तो संभव है लेकिन संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। वहीं 2024 में बलराम सिंह बनाम भारत सरकार केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को हटाने की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ बदल सकता है और संसद को संशोधन का अधिकार है बशर्ते वह मूल संरचना को क्षति न पहुंचाए। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि भारत का धर्मनिरपेक्ष चरित्र संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में निहित है और राज्य किसी धर्म विशेष का समर्थन नहीं करेगा।

लेकिन वैचारिक तौर पर यह बहस अभी समाप्त नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी और उसके वैचारिक स्रोत संघ के अनेक नेताओं का मानना है कि 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द भारत की बहुसंख्यक परंपरा को नकारता है और इसके जरिए तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा मिला है। वहीं समाजवाद के नाम पर सरकारी नियंत्रण, लाइसेंस राज और निजी उद्यमिता के दमन का इतिहास भी याद दिलाया जाता है। दूसरी ओर, कांग्रेस और विपक्षी दलों का कहना है कि ये शब्द संविधान के आदर्शों की व्याख्या करते हैं और भारत की विविधता को संरक्षण देते हैं। उनका मानना है कि यदि इन शब्दों को हटाया गया तो संविधान की आत्मा को गहरी चोट पहुंचेगी और यह देश को विभाजित करने वाली सोच की ओर ले जाएगा।

इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को लेकर चल रही बहस केवल दो शब्दों की नहीं, बल्कि देश की वैचारिक दिशा की है। यह बहस तय करेगी कि भारत की पहचान आने वाले वर्षों में कैसी होगी क्या हम विविधता में एकता को बनाए रखेंगे या किसी एकरूपता की ओर बढ़ेंगे? यह बहस इस बात को भी स्पष्ट करेगी कि क्या संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो समय के साथ बदलता है या फिर वह पत्थर की लकीर है। यह बहस केवल नेताओं और अदालतों की नहीं, बल्कि देश की जनता की है। यह फैसला भारत के नागरिकों को करना है कि वे किस प्रकार का भारत चाहते हैं एक ऐसा भारत जो सबको साथ लेकर चले या एक ऐसा भारत जो एक सोच, एक दिशा और एक रंग में ढला हो। इसलिए यह जरूरी है कि इस बहस को केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि संवैधानिक और नैतिक आधार पर देखा जाए ताकि हमारा लोकतंत्र और

संविधान में समाजवाद-धर्मनिरपेक्षता की एंट्रीः इंदिरा की विरासत या साजिश

संजय सक्सेना
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस ने आरएसएस पर निशाना क्या साधा, भारतीय राजनीति में भूचाल ही आ गया। कांग्रेस ने तुरंत आरोप लगा दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की सोच ही संविधान विरोधी है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'ये बाबा साहेब के संविधान को खत्म करने की वो साजिश है, जो आरएसएस–बीजेपी हमेशा से रचती आई है।' इससे पहले दत्तात्रेय होसबोले ने एक कार्यक्रम में कहा था कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था और इन्हें प्रस्तावना में रहना चाहिए या नहीं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। होसबाले के इस बयान के बाद इंडी गठबंधन के धड़े और बीजेपी आमने–सामने आ गई है। कांग्रेस तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इस बदलाव का बचाव करने के लिए इंदिरा की जगह बाबा साहब के पीछे छिपकर भाजपा और संघ नेताओं के खिलाफ हमलावर है, वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की सांप्रदायिक सोच बताकर उस पर हमलावर है।

गौरतलब हो, भारत का संविधान, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, एक जीवंत और गतिशील दस्तावेज है। यह न केवल देश के शासन की नींव है, बल्कि समय के साथ समाज की बदलती जरूरतों को भी दर्शाता है। संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों का समावेश एक ऐसी राजनीतिक घटना है, जो कथित तौर पर भारतीय लोकतंत्र की प्रगतिशीलता और दूरदर्शिता को रेखांकित करती है। इस हकीकत से इंकार नहीं किया जा सकता है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की एंट्री न तो महात्मा गांधी, न ही बाबा साहब अंबेडकर की देन है, बल्कि इसकी बुनियाद भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी थी।

15 अगस्त 1947 को देश आजाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तो यह भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करने वाला दस्तावेज था। डॉ. अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा ने इसे एक

ऐसा ढांचा दिया, जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था। महात्मा गांधी के विचारों ने भी संविधान की भावना को प्रभावित किया, खासकर सामाजिक न्याय और अहिंसा के क्षेत्र में।

हालांकि, प्रारंभिक संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द स्पष्ट रूप से शामिल नहीं थे। यह अनुपस्थिति न तो किसी कमी को दर्शाती थी, न ही किसी विचारधारा की अनदेखी को। यह उस समय की परिस्थितियों का परिणाम था, जब संविधान को एक व्यापक और लचीला दस्तावेज बनाने की जरूरत थी।

1966 में, जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनीं, देश एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। आजादी के बाद के दशकों में भारत ने आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना किया। गरीबी, असमानता और सामाजिक भेदभाव जैसे मुद्दे देश के सामने थे। इंदिरा ने इन समस्याओं को देखा और महसूस किया कि भारत को एक ऐसी दिशा की जरूरत है, जो न केवल आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करे, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता को भी बढ़ावा दे। इसके साथ ही, भारत की बहु–धार्मिक और बहु–सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने की आवश्यकता थी, ताकि सभी धर्मों और समुदायों के बीच सामंजस्य बना रहे।

इंदिरा गांधी का नेतृत्व साहस और दूरदर्शिता से भरा था। उन्होंने गरीबी हटाओ जैसे नारे दिए, जो समाजवादी विचारधारा का प्रतीक बन गए। उनका मानना था कि भारत का विकास तभी संभव है, जब समाज के सबसे कमजोर वर्ग को मुख्यधारा में लाया जाए। लेकिन यह केवल नारों तक सीमित नहीं था। इंदिरा ने इसे संवैधानिक स्तर पर स्थापित करने का निर्णय लिया।

1976 में, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत के संविधान में 42वां संशोधन पारित हुआ। यह संशोधन भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक था। इस संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में दो महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। इसके साथ ही, भारत

कांग्रेस ने तुरंत आरोप लगा दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की सोच ही संविधान विरोधी है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'ये बाबा साहेब के संविधान को खत्म करने की वो साजिश है, जो आरएसएस-बीजेपी हमेशा से रचती आई है।'

को अब संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित किया। समाजवादी शब्द का समावेश इंदिरा गांधी के उस दृष्टिकोण को दर्शाता था, जिसमें आर्थिक और सामाजिक समानता सर्वोपरि थी। यह समाजवाद मार्क्सवादी या साम्यवादी विचारधारा से अलग था। यह भारतीय संदर्भ में समाजवाद था, जो लोकतंत्र के साथ सामंजस्य बिठाता था। इसका उद्देश्य था कि संसाधनों का वितरण इस तरह हो कि समाज का हर वर्ग, विशेष रूप से गरीब और वंचित, इसका लाभ उठा सके। इंदिरा के नेतृत्व में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जमींदारी उन्मूलन और ग्रामीण विकास योजनाएं इस समाजवादी दृष्टिकोण का हिस्सा थीं। संविधान में इस शब्द को जोड़कर उन्होंने इसे एक स्थायी और संवैधानिक आधार दिया।

विरोध की जड़ें कई स्तरों पर हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बाबा साहब ने संविधान बनाते समय समाजवाद और धर्म–निरपेक्षता को स्पष्ट रूप से प्रस्तावना में शामिल नहीं किया, क्योंकि वे चाहते थे कि संविधान तटस्थ रहे। उनके लिए संविधान सामाजिक और आर्थिक बदलाव का उपकरण था, न कि किसी विचारधारा का प्रचारक। आलोचकों का कहना है कि इंदिरा गांधी ने इन शब्दों को जोड़कर अपनी सरकार की समाजवादी नीतियों को संवैधानिक समर्थन देने की कोशिश की, जो आपातकाल जैसे अलोकतांत्रिक कदमों के साथ विरोधाभासी थी।

धर्मनिरपेक्षता को लेकर भी सवाल उठे। भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब 'सर्वधर्म समभाव' रहा है, लेकिन कुछ लोग इसे पश्चिमी 'सेक्युलरिज्म' से जोड़कर देखते हैं, जो धर्म को सार्वजनिक जीवन से अलग करता है। हिंदू राष्ट्रवादी समूहों का मानना है कि यह शब्द बहुसंख्यक हिंदू संस्कृति को कमजोर करता है। दूसरी ओर, अल्पसंख्यक समुदाय इसे अपनी सुरक्षा का आधार मानते हैं। इस तरह, धर्मनिरपेक्षता एक ध्रुवीकृत मुद्दा बन गया।

समाजवाद पर भी बहस जारी है। कुछ लोग इसे आर्थिक सुधारों के खिलाफ मानते हैं, जो 1991 में शुरू हुए। वे कहते हैं कि समाजवाद का शब्द अब प्रासंगिक नहीं, क्योंकि भारत ने बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाया है। दूसरी ओर, समाजवादी विचारकों का कहना है कि यह शब्द संविधान को सामाजिक न्याय का दिशा–निर्देश देता है। आज, जब लोग इन शब्दों का विरोध करते हैं, तो वे इंदिरा गांधी की मंशा पर सवाल उठाते हैं। क्या यह वास्तव में देशहित में था या सत्ता को मजबूत करने की रणनीति? बाबा साहब का संविधान समावेशी था, लेकिन क्या इन शब्दों ने उसकी मूल भावना को बदला? यह बहस भारत के भविष्य को भी प्रभावित करती है, क्योंकि यह तय करती है कि हमारा संविधान किस विचारधारा को अपनाएगा।

धर्मनिरपेक्षता एकता का आधार

धर्मनिरपेक्ष शब्द का समावेश भारत की बहु–धार्मिक और बहु–सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने का एक प्रयास था। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता और सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है।

यह शब्द संविधान में जोड़कर इंदिरा ने यह सुनिश्चित किया कि भारत की एकता और अखंडता को कोई धार्मिक या सांप्रदायिक शक्ति कमजोर न कर सके। यह विशेष रूप से उस समय महत्वपूर्ण था, जब सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव देश के लिए चुनौती बन रहे थे। 42 वां संशोधन और इंदिरा गांधी के इस कदम की आलोचना भी हुई। कुछ लोगों का मानना था कि यह संशोधन आपातकाल के दौरान लागू किया गया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के

सुविधा और दुविधा में फंसी यूपी के बेसिक शिक्षकों की तबादला नीति

संजय सक्सेना
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए सात साल बाद तबादले खोलकर शिक्षक समाज को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार द्वारा अंतर–जनपदीय और जिला–स्तरीय तबादलों का रास्ता खुलने से शिक्षक खुश तो हैं, लेकिन इसमें वह (शिक्षक) कुछ कमियों की बात करते हुए इन्हें दूर करने की बात भी कह रहे हैं। तबादला प्रक्रिया शिक्षकों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित थी, क्योंकि कई शिक्षक अपने गृह जनपद या परिवार के नजदीक स्थानांतरित होने की उम्मीद में वर्षों से इंतजार कर रहे थे। इस प्रक्रिया की शुरुआत जून 2025 में हुई, जब बेसिक शिक्षा परिषद ने शिक्षकों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन जैसे–जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ी, शिक्षकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके उत्साह को निराशा में बदल दिया है।

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में लाखों शिक्षक कार्यरत हैं, और इनमें से कई अपने गृह जनपद से सैकड़ों किलोमीटर दूर तैनात हैं। परिवार से दूरी, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्ग माता–पिता की देखभाल और अन्य सामाजिक जिम्मेदारियों के कारण शिक्षक लंबे समय से तबादले की मांग कर रहे थे। सात साल बाद जब सरकार ने तबादलों की अनुमति दी, तो शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई। बेसिक शिक्षा परिषद ने 9 से 12 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे, और आवेदन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए मानव संपदा पोर्टल का उपयोग किया गया। इसके बाद 13 जून तक आवेदन के प्रिंट–आउट जमा करने और 16 जून को तबादला सूची जारी करने की तारीख तय की गई थी। लेकिन जैसे ही शिक्षकों ने आवेदन शुरू किए, तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं ने उनका रास्ता रोक लिया। सबसे बड़ी परेशानी जो शिक्षकों को हुई, वह थी मानव संपदा पोर्टल की तकनीकी खामियां। कई शिक्षकों ने शिकायत की कि पोर्टल पर उनकी जानकारी गलत दर्ज थी, जैसे कि उनकी सेवा अवधि, जन्म तिथि, या वर्तमान तैनाती का विवरण। कुछ शिक्षकों की मानव संपदा आईडी ही अपडेट नहीं थी, जिसके कारण वे आवेदन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सके। इसके अलावा, पोर्टल पर अचानक सर्वर डाउन होने की समस्या ने भी शिक्षकों को परेशान किया। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले शिक्षकों के लिए यह और भी मुश्किल था, क्योंकि उनके पास इंटरनेट की सुविधा सीमित थी। कई शिक्षकों को साइबर कैफे का सहारा लेना पड़ा, जहां उन्हें अतिरिक्त खर्च और समय की बर्बादी का सामना करना पड़ा।

एक और बड़ी समस्या थी तबादले के लिए सीमित जिला विकल्प। बेसिक शिक्षा विभाग ने अंतर–जनपदीय तबादलों के लिए केवल 15 जिलों का विकल्प दिया, जबकि 60 अन्य जिलों में तबादले के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किए गए। इससे उन शिक्षकों में निराशा फैल गई, जो अपने गृह जनपद या परिवार के नजदीक किसी विशेष जिले में जाना चाहते थे। विभाग ने यह तर्क दिया कि इन 15 जिलों में शिक्षकों की कमी है, और इसलिए प्राथमिकता इन्हीं जिलों को दी गई। लेकिन शिक्षकों का कहना था कि यह फैसला एकतरफा था और उनकी

व्यक्तिगत जरूरतों को नजरअंदाज किया गया। कुछ शिक्षकों ने तो यह भी आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। यही वजह है तबादला सूची जारी होने के बाद भी परेशानियां कम नहीं हुईं।

कई शिक्षकों को उनके द्वारा चुने गए विकल्पों से अलग जिलों में स्थानांतरित कर दिया गया। कुछ मामलों में, शिक्षकों को ऐसे स्कूलों में भेजा गया, जहां बुनियादी सुविधाएं, जैसे कि बिजली, पानी, या शौचालय, भी उपलब्ध नहीं थे। इससे खासकर महिला शिक्षकों को ज्यादा परेशानी हुई, क्योंकि उनके लिए नए स्थान पर रहना और काम करना असुरक्षित था। इसके अलावा, तबादले के बाद भी कई शिक्षकों को रिलीव नहीं किया गया। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक का तबादला पीलीभीत के एक प्राथमिक विद्यालय में हुआ, लेकिन उनके मूल स्कूल ने उन्हें छोड़ने से इनकार कर दिया, जिससे वे न तो नए स्कूल में जॉइन कर सके और न ही पुराने स्कूल में नियमित रूप से काम कर पाए।

तबादलों के दौरान वेतन संबंधी समस्याएं भी शिक्षकों के लिए सिरदर्द बनीं। तबादले के बाद कई शिक्षकों की मानव संपदा आईडी और लास्ट पे सर्टिफिकेट (एलपीसी) ट्रांसफर नहीं हुए, जिसके कारण उनका जून 2025 का वेतन रुक गया। यह समस्या खासकर उन शिक्षकों के लिए गंभीर थी, जो आर्थिक रूप से कमजोर थे और परिवार का खर्च चलाने के लिए वेतन पर निर्भर थे। शिक्षकों ने इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर भी अपनी नाराजगी जताई, और कई ने बेसिक शिक्षा परिषद से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। लेकिन विभाग की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिला, जिससे शिक्षकों का गुस्सा और बढ़ गया। प्रशासनिक स्तर पर भी तबादलों में कई अनियमितताएं देखी गईं।

कुछ शिक्षकों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रभावशाली लोग अपने रसूख का इस्तेमाल कर मनचाहे स्थानों पर तबादला करवा रहे थे, जबकि सामान्य शिक्षकों को अनदेखा किया जा रहा था। इसके अलावा, तबादला प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी ने भी शिक्षकों का

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में लाखों शिक्षक कार्यरत हैं, और इनमें से कई अपने गृह जनपद से सैकड़ों किलोमीटर दूर तैनात हैं। परिवार से दूरी, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल और अन्य सामाजिक जिम्मेदारियों के कारण शिक्षक लंबे समय से तबादले की मांग कर रहे थे।

भरोसा तोड़ा। कई शिक्षकों को यह समझ नहीं आया कि उनकी प्राथमिकता के बावजूद उन्हें दूसरा जिला क्यों मिला। कुछ शिक्षकों ने तो यह भी कहा कि तबादला सूची में उनके नाम ही गायब थे, जबकि उन्होंने समय पर आवेदन किया था।

इसके अलावा, सरकार के हाल के फैसले ने भी शिक्षकों को और परेशान कर दिया क्योंकि एक तरफ शिक्षकों के तबादले खोले गये तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग में तबादलों पर अस्थायी रोक लगा दी गई। इसका कारण स्कूल चलो अभियान और अन्य विभागीय कार्यों को सुचारू रूप से चलाना बताया गया। शिक्षकों का कहना था कि यह रोक उनके साथ नाइंसाफी है, तबादला प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी और कई शिक्षक नए स्कूलों में जॉइन करने की तैयारी कर रहे थे। उन शिक्षकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जो अपने परिवार के करीब जाने का सपना देख रहे थे। अधिकांश शिक्षकों का कहना है कि योगी सरकार की तबादला नीति से उन्हें सुविधा कम दुविधा जैसा हो रही है। शिक्षकों की इन परेशानियों ने बेसिक शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। एक ओर, सरकार ने तबादलों को पारदर्शी और शिक्षक हित में बताया, लेकिन दूसरी ओर, तकनीकी खामियां, सीमित विकल्प, और प्रशासनिक अनियमितताओं ने इस प्रक्रिया को जटिल बना दिया। शिक्षकों का कहना है कि अगर विभाग ने पहले से तैयारी की होती, तो ये समस्याएं नहीं आतीं। यह भी मांग की है कि तबादला प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाए, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। बहरहाल, तबादला चाहने वाले शिक्षक अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी परेशानियां जल्द दूर होंगी।

तबादला प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी

सरकार ने 24 मई 2025 को नई तबादला नीति जारी की, जिसमें 5 साल की न्यूनतम सेवा अवधि की बाध्यता हटा दी गई। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक शिक्षकों को तबादले का अवसर देना था, खासकर उन नए शिक्षकों को जो 68500 और 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित हुए थे। विभाग का दावा है कि इस नीति से 6 लाख से अधिक शिक्षक लाभान्वित होंगे। वहीं तबादला प्रक्रिया में आ रही समस्याओं के संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना था कि शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे ऑनलाइन आवेदन, सेवा अवधि की बाध्यता हटाना, और आवेदन तारीख बढ़ाना आदि शमिल है। हालांकि, तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियों के कारण कुछ समस्याएं आई हैं, जिन्हें हल करने के लिए विभाग काम कर रहा है। तबादलों पर अस्थायी रोक को सरकार ने विभागीय कार्यों की प्राथमिकता के रूप में उचित ठहराया है। शिक्षकों की शिकायतों के बावजूद, सरकार का दावा है कि यह प्रक्रिया उनके हित में है और जल्द ही बाकी मुद्दों का समाधान कर लिया जाएगा।

खाली पड़े हैं 85152 सहायक अध्यापक पद

उत्तर प्रदेश सरकार ने 06 फरवरी में बजट सत्र के दौरान विधानसभा में बताया था कि राज्य में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के 85152 पद रिक्त हैं। हालांकि, शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को मिलाकर छात्र–शिक्षक का अनुपात पूरा है और पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। विभाग में शिक्षा मित्र, अनुदेशक और सहायक अध्यापकों को मिलाकर वर्तमान में शिक्षकों की संख्या 6,28,915 है। संचालित प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के 85152 पद रिक्त हैं। प्रदेश के परिषदीय प्राइमरी स्कूलों में कुल 4,59,450 शिक्षक हैं। इनमें 3,38,590 प्राइमरी में है जबकि 1,20, 860 शिक्षक

प्रयागराज में दलित बच्चियों का धर्म बदलकर आतंकवादी बनाने की साजिश का बड़ा खुलासा

संजय सक्सेना
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ

उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जो एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर है,उसमें हाल ही में एक सनसनीखेज और चिंताजनक घटना के कारण सुर्खियों में आया है। पुलिस ने एक खतरनाक साजिश का पर्दाफाश किया है, जिसमें दलित नाबालिग लड़कियों को बहला–फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने और उन्हें आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने की योजना थी। इस मामले ने न केवल स्थानीय समुदाय को झकझोर दिया है, बल्कि पूरे देश में सामाजिक और धार्मिक संवेदनशीलता पर सवाल उठाए हैं।

यह सनसनीखेज मामला तब सामने आया जब प्रयागराज पुलिस को सूचना मिली कि फूलपुर इलाके में एक दलित नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे पहले दिल्ली और फिर केरल ले जाया गया। जांच में पता चला कि इस अपहरण के पीछे एक सुनियोजित साजिश थी, जिसका उद्देश्य नाबालिग लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना और उन्हें आतंकवादी संगठनों में भर्ती करना था। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और लड़की को सुरक्षित बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया।

आरोपियों ने कथित तौर पर लड़की को बहला–फुसलाकर पहले दिल्ली ले गए, जहां उसे मानसिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश की गई। इसके बाद उसे केरल ले जाया गया, जहां उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराने और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने की योजना थी। इस साजिश में शामिल लोगों ने नाबालिगों को निशाना बनाया, उन्हें लगता था कि कम उम्र की लड़कियां आसानी से प्रभावित हो सकती हैं।

जांच से पता चला कि यह गिरोह विशेष रूप से दलित समुदाय की नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाता था। इन लड़कियों को पहले लालच देकर या भावनात्मक रूप से प्रभावित करके अपने जाल में फंसाया जाता था। इसके बाद, उन्हें उनके परिवारों से दूर ले जाकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला जाता था। इस साजिश का अंतिम लक्ष्य इन लड़कियों को आतंकवादी संगठनों के लिए तैयार करना था, ताकि वे जिहादी गतिविधियों में शामिल हो सकें। यह खुलासा न केवल सामाजिक दृष्टिकोण से गंभीर है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा है।

आरोपियों ने कथित तौर पर लड़की को बहला-फुसलाकर पहले दिल्ली ले गए, जहां उसे मानसिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश की गई। इसके बाद उसे केरल ले जाया गया, जहां उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराने और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने की योजना थी।

प्रयागराज पुलिस ने इस मामले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की। सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और अपहरण के कुछ ही समय बाद लड़की को केरल से बरामद कर लिया। इस ऑपरेशन में शामिल पुलिसकर्मियों ने अपनी सूझबूझ और तत्परता से एक बड़े खतरे को टाल दिया। गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों से पूछताछ जारी है, और पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस साजिश में और कौन–कौन शामिल हो सकता है। पुलिस का मानना है कि यह एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा हो सकता है, जिसके तार देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े हो सकते हैं।

इस घटना ने सामाजिक और धार्मिक स्तर पर कई सवाल खड़े किए हैं। दलित समुदाय, जो पहले से ही सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, अब इस तरह की साजिशों का शिकार बन रहा है। यह घटना समाज में विश्वास की कमी को और गहरा सकती है। साथ ही, धर्म परिवर्तन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर यह मामला एक नई बहस को जन्म दे सकता है। कई संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस घटना की निंदा की है और सरकार से ऐसी साजिशों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। अब देखना यह है हर समय ओबीसी और पीडीए का राग अलापने वाले नेता इस मसले पर कुछ बोलते हैं या फिर तुष्टिकरण की सियासत के चलते पहले की तरह इस समय भी मुंह बंद रखेंगे।

देशभर में पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 की शुरुआत

ई-पासपोर्ट को बताया गया बड़ी उपलब्धि

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पूरे देश में पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (PSP) 2.0 की शुरुआत की और इसे एक बड़ी प्रगति करार दिया। उन्होंने पासपोर्ट विभाग से जुड़े सभी कर्मचारियों और सहयोगियों को उनके समर्पण और कार्यकुशलता के लिए बधाई दी।

13वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर उन्होंने भारत और विदेशों में कार्यरत सभी पासपोर्ट अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि ई–पासपोर्ट की शुरुआत और पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के अगले चरण की घोषणा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

उन्होंने कहा, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मूलमंत्र पर आधारित आपके प्रयासों ने नागरिकों की यात्रा को सहज बनाया है, वैश्विक अवसरों की पहुंच बढ़ाई है और आम लोगों को सशक्त किया है। विदेश मंत्रालय (PSP) 2.0 और ई–पासपोर्ट जैसी पहलों के माध्यम से समयबद्ध, पारदर्शी और सुलभ पासपोर्ट सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है।

सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के स्तंभ

'X' (एक्स) पर पोस्ट करते हुए जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा में हुए सुधार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण जैसे शासन के तीन प्रमुख स्तंभों को दर्शाते हैं, जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं।

एक दशक में सेवा में बड़ा बदलाव

विदेश मंत्री ने बताया कि 2014 में जहाँ 91 लाख पासपोर्ट जारी हुए थे, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर 1.46 करोड़ हो गई है। उन्होंने बताया कि च्चे ट2.0 को देशभर में लागू कर दिया गया है, जिसमें दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है।

विदेशों में भी शुरू होगा (PSP)2.0

उन्होंने कहा, ष्भारत सरकार की नागरिक–केन्द्रित सेवा की प्रतिबद्धता के अनुरूप (PSP) 2.0 अब देशभर में लागू हो चुका है। विदेशों में भी इसका पायलट परीक्षण जारी है और इसे चरणबद्ध तरीके से सभी दूतावासों व वाणिज्य दूतावासों में लागू किया जाएगा।

ई-पासपोर्टः एक बड़ी उपलब्धि

जयशंकर ने कहा कि ई–पासपोर्ट, जो संपर्क रहित चिप तकनीक पर आधारित है, यात्रा को सुगम बनाता है और इमिग्रेशन प्रक्रिया को तेज करता है। इसके साथ ही उन्होंने उंच्वतज च्वसपबम ।चच का जिक्र किया, जिसकी मदद से 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस सत्यापन का समय 5–7 दिनों तक घट गया है।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि मोबाइल वैन के जरिए दूरस्थ क्षेत्रों में भी पासपोर्ट सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं, जिससे वहां के नागरिकों को अब सुविधाएं आसानी से मिल रही हैं।

अमित शाह ने मौर्य को 'मेरे मित्र' पुकारा तो छिड़ गई सियासी चर्चा

अजय कुमार
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ

कार्यक्रम की शुरुआत में अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा, इस ऐतिहासिक अवसर पर मेरे साथ उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा मेरे मित्र और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी मंच पर उपस्थित हैं।यह छोटा सा वाक्य ही पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को झकझोरने के लिए काफी था॥

लखनऊ में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह ने जहां हजारों युवाओं के जीवन में एक नई शुरुआत की उम्मीद जगाई, वहीं राजनीति के गलियारों में इस कार्यक्रम ने जबरदस्त हलचल भी पैदा कर दी। वजह केवल यह नहीं थी कि राज्य सरकार द्वारा इतनी बड़ी संख्या में पारदर्शी तरीके से नौकरियों का वितरण हुआ, बल्कि इस मंच से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा बोले गए कुछ शब्द ऐसे थे, जिनका राजनीतिक अर्थ निकालने में नेता से लेकर विश्लेषक तक जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कौन कितना भारी और किसकी स्थिति कितनी मजबूत है, इसका पैमाना अब केवल चुनावी आंकड़ों से नहीं बल्कि मंच पर बोले गए संबोधनों और दी गई उपाधियों से भी तय होने लगा है। यही कारण है कि अमित शाह द्वारा उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को 'मेरे मित्र' कहकर पुकारना इतना बड़ा मुद्दा बन गया है।

लखनऊ में आयोजित इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में अमित शाह के साथ मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे। मंच की व्यवस्था भी प्रतीकात्मक थी अमित शाह बीच में, उनके दाएं योगी और बाएं मौर्य। कार्यक्रम की शुरुआत में अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा, इस ऐतिहासिक अवसर पर मेरे साथ उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा मेरे मित्र और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी मंच पर उपस्थित हैं।ष्यह छोटा सा वाक्य ही पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को झकझोरने के लिए काफी था। एक तरफ यह योगी आदित्यनाथ को 'लोकप्रिय और सफल' कहकर मुख्यमंत्री पद पर उनके अधिकार को पुष्ट करता है, तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य को 'मित्र' कहकर पार्टी के भीतर उनके महत्व को एक तरह से सार्वजनिक समर्थन प्रदान करता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस एक शब्द में कई संदेश छिपे हैं। सबसे पहले तो यह स्पष्ट होता है कि दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व की नजरें अभी भी योगी आदित्यनाथ पर पूरी तरह टिकी हैं और उनके नेतृत्व पर सवाल उठाने वालों को यह समझाने की कोशिश की गई है

कि मुख्यमंत्री का चेहरा फिलहाल बदले जाने की कोई योजना नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी से अपेक्षित परिणाम न मिलने पर जब कुछ नेताओं ने योगी आदित्यनाथ पर अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदारी डालने की कोशिश की थी, तब भी खुद अमित शाह ने सार्वजनिक रूप से योगी की भूमिका की सराहना की थी। अब जबकि विधानसभा चुनाव 2027 की दिशा में भाजपा अपनी तैयारी तेज कर रही है, ऐसे में पार्टी के भीतर किसी प्रकार के भ्रम या टकराव की संभावना खत्म करने की कोशिश हो रही है।

वहीं दूसरी ओर, अमित शाह द्वारा केशव प्रसाद मौर्य को मित्र कहना केवल औपचारिक संबोधन नहीं था। यह उस वर्ग विशेष के लिए एक सधा हुआ राजनीतिक संदेश था, जिसे मौर्य प्रतिनिधित्व करते हैं। ओबीसी वर्ग, खासकर कुशवाहा और मौर्य समुदाय में केशव प्रसाद मौर्य की पकड़ मजबूत मानी जाती है। 2017 में जब बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, तब मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे और उनकी रणनीति से भाजपा ने पिछड़े वर्गों में गहरी पैठ बनाई थी। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में सिराथू से उनकी हार के बाद उनके प्रभाव को लेकर सवाल उठने लगे थे, परंतु संगठन में उनका महत्व बना रहा। अमित शाह द्वारा उन्हें मित्र कहे जाने से यह स्पष्ट संकेत दिया गया है कि भले ही वह चुनाव हार गए हों, परंतु पार्टी में उनका राजनीतिक महत्व कम नहीं हुआ है।

यह भी समझना जरूरी है कि अमित शाह जैसे रणनीति कार कोई भी शब्द यूं ही मंच से नहीं बोलते। 'मित्र' शब्द आमतौर पर तब प्रयोग किया जाता है जब निजी संबंधों को दर्शाना हो और सार्वजनिक रूप से किसी के प्रति सम्मान जताना हो। इस लिहाज से यह बयान कई मायनों में मौर्य के लिए सम्मान सूचक था और उन तमाम चर्चाओं को खारिज करने की कोशिश थी जिनमें कहा जा रहा था कि पार्टी में अब मौर्य की स्थिति कमजोर हो रही है। यह भी एक प्रकार का संतुलन बैठाने की कोशिश कही जा सकती है एक तरफ योगी को पूरी ताकत से

यह भी समझना जरूरी है कि अमित शाह जैसे रणनीति कार कोई भी शब्द यूं ही मंच से नहीं बोलते। 'मित्र' शब्द आमतौर पर तब प्रयोग किया जाता है जब निजी संबंधों को दर्शाना हो और सार्वजनिक रूप से किसी के प्रति सम्मान जताना हो।

समर्थन देना और दूसरी ओर मौर्य को भी सम्मानपूर्वक साथ रखना।

लेकिन इस राजनीतिक संदेश का असर केवल भाजपा तक सीमित नहीं रहा। विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी ने इसे तुरंत भांप लिया और इस पर तंज भी कसा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, "इन्होंने इश्तहार में न लगाया उनका चित्र, उन्होंने किसी और को कह दिया 'मित्र'!" अखिलेश का यह तंज जितना अमित शाह पर था, उतना ही भाजपा के आंतरिक समीकरणों पर भी। लेकिन भाजपा के नेताओं ने भी तुरंत पलटवार किया और कहा कि विपक्ष को न समझ में आता है न स्वीकार होता है कि भाजपा के नेताओं में आपसी सहयोग और सम्मान का रिश्ता है।

राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो अमित शाह का यह संबोधन आगामी चुनाव की भूमिका को मजबूत करने वाला कदम है। बीजेपी अब न केवल अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवा रही है, बल्कि समाजिक समीकरणों को भी सधे तरीके से साधने की कोशिश कर रही है। योगी आदित्यनाथ को जहां हिंदुत्व और कानून–व्यवस्था के प्रतीक के रूप में आगे रखा जा रहा है, वहीं मौर्य को ओबीसी वर्ग की भावनाओं और प्रतिनिधित्व का चेहरा बनाकर एक संतुलन बनाने की कवायद की जा रही है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति जातीय समीकरणों से बहुत अधिक प्रभावित होती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार जाति जनगणना की मांग को लेकर भाजपा पर हमला बोलते रहे हैं। खासकर ओबीसी वर्ग के मुद्दों को लेकर विपक्ष की रणनीति काफी आक्रामक रही है। ऐसे में भाजपा की तरफ से मौर्य को मंच पर विशेष संबोधन देना यह दर्शाता है कि पार्टी अपने ओबीसी चेहरे को कमजोर नहीं दिखाना चाहती। यही वजह है कि कार्यक्रम के दौरान और बाद में अमित शाह ने मौर्य के प्रति सार्वजनिक तौर पर सकारात्मक भाव दर्शाए।

यह भी उल्लेखनीय है कि हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला करते हुए कहा था कि 2027 में सपा का अंतिम अध्याय लिखा जाएगा। इसके जवाब में सपा सांसद राजीव राय ने पलटवार करते हुए कहा कि केशव मौर्य अब 2057 तक भी कोई चुनाव नहीं जीत पाएंगे। यह जुबानी जंग बताती है कि दोनों दलों के बीच मुकाबला अब व्यक्तिगत स्तर तक उतर आया है। यह भी समझा जा सकता है कि मौर्य की राजनीतिक सक्रियता केवल सांकेतिक नहीं, बल्कि आगामी चुनावों की रणनीति का हिस्सा है।

इस पूरे घटनाक्रम को देखकर एक बात तो स्पष्ट है कि भाजपा नेतृत्व अब किसी भी प्रकार की अंदरूनी असंतुलन की स्थिति को जन्म नहीं देना चाहता। पार्टी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि चुनाव से पहले एकजुटता का प्रदर्शन हो और हर वर्ग को संतुलित प्रतिनिधित्व मिले। इसी रणनीति का हिस्सा है अमित शाह का श्मेरे मित्रश वाला संबोधन जिसमें सम्मान है, संदेश है और सियासी संतुलन भी।

लखनऊ का यह कार्यक्रम केवल नियुक्ति पत्र वितरण तक सीमित नहीं रहा। इस मंच से जो शब्द बोले गए, उनका असर दूर तक गया। अमित शाह ने एक ओर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर फिर से भरोसा जताया, तो दूसरी ओर केशव प्रसाद मौर्य के राजनीतिक कद को गिरने से रोक लिया। सियासत में 'दो कदम आगे और एक कदम पीछे' की चाल के बीच यह भाषण भाजपा की रणनीतिक परिपक्वता का प्रमाण बनकर उभरा है। अब देखना होगा कि इस संतुलन का असर पार्टी के आगामी फैसलों और चुनावी रणनीतियों पर कितना गहरा पड़ता है। लेकिन इतना तो तय है कि श्मेरे मित्रश अब केवल एक संबोधन नहीं, बल्कि एक राजनीतिक घोषणापत्र जैसा

प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की बातचीत विदेश नीति की परिपक्वता की मिसाल

लगभग 35 मिनट तक चली इस बातचीत में न सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा हुई, बल्कि भारत-पाकिस्तान तनाव, अश्वपरेशन सिंदूर और भारत-अमेरिका संबंधों की दिशा को लेकर भी बड़े स्तर पर रणनीतिक विमर्श सामने आया।

अजय कुमार
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई हालिया टेलीफोनिक बातचीत वैश्विक कूटनीति और भारत की विदेश नीति के लिहाज से एक अहम मोड़ साबित हुई है। लगभग 35 मिनट तक चली इस बातचीत में न सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा हुई, बल्कि भारत–पाकिस्तान तनाव, ऑपरेशन सिंदूर और भारत–अमेरिका संबंधों की दिशा को लेकर भी बड़े स्तर पर रणनीतिक विमर्श सामने आया। हालांकि यह मुलाकात जी7 सम्मेलन के दौरान आमने–सामने होने वाली थी, लेकिन ट्रंप की अमेरिका वापसी के कारण दोनों नेताओं को फोन पर बात करनी पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प और चर्चित पहलू यह रहा कि ट्रंप के अमेरिका आने के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री मोदी ने विनम्रता पूर्वक ठुकरा दिया, और इसकी वजह सिर्फ राजनयिक व्यस्तता नहीं थी, बल्कि गहरी रणनीतिक सूझबूझ और राजनीतिक परिपक्वता भी इसके पीछे काम कर रही थी।

बातचीत की शुरुआत ट्रंप के उस अनुरोध से हुई जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया कि वे कनाडा से लौटते समय अमेरिका रुकते हुए जाएं और व्हाइट हाउस में उनसे मिलें। परंतु, पीएम मोदी ने यह न्योता यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि उन्हें अपनी पहले से तय क्रोएशिया यात्रा के लिए निकलना है। यह निर्णय सिर्फ औपचारिक कारणों से नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक संकेत छुपा हुआ था। दरअसल, उसी दिन ट्रंप के साथ पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की लंच पर बैठक पहले से निर्धारित थी। ऐसे में पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा राजनीतिक रूप से भारत के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकती थी। एक ही दिन, एक ही जगह भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के फौजी प्रमुख का उपस्थित

होना न केवल भारत की कूटनीतिक स्थिति को कमजोर करता, बल्कि वैश्विक पटल पर गलत संदेश भी जाता।

इस बातचीत में ऑपरेशन सिंदूर विशेष चर्चा का विषय रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को विस्तार से बताया कि कैसे भारत ने 6–7 मई की रात पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि यह सैन्य कार्रवाई सटीक, नपी–तुली और गैर–भड़काऊ थी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि भारत अब आतंकवाद को एक सीमित 'प्रॉक्सी वॉर' नहीं, बल्कि एक पूर्ण युद्ध के रूप में देखता है। मोदी ने बताया कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत ने गोले से दिया है, और यह नीति भविष्य में भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने ट्रंप से यह भी कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में कभी भी अमेरिका की ओर से कोई मध्यस्थता नहीं हुई, न ही भारत ने इसकी कोई मांग की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत ने कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है, और न भविष्य में करेगा। यह बात भारत की विदेश नीति की आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान को दर्शाती है। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बाद में इस बातचीत की जानकारी साझा करते हुए बताया कि सैन्य कार्रवाई को रोकने की बात भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच सीधे सैन्य चौनल के जरिए हुई थी, और वह भी पाकिस्तान के आग्रह पर।

इस वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने ट्रंप को क्वाड की अगली बैठक के लिए भारत आने का न्योता भी दिया। ट्रंप ने यह न्योता स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने को लेकर उत्सुक हैं। इसके अतिरिक्त दोनों नेताओं ने इजरायल–ईरान तनाव, रूस–यूक्रेन युद्ध और हिंद–प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर भी विचार साझा किए। खासकर हिंद–प्रशांत क्षेत्र में क्वाड की भूमिका को लेकर दोनों की सोच में समानता दिखी, और इस पर भविष्य में मिलकर काम करने की बात कही गई। इस बातचीत में एक और महत्वपूर्ण पहलू अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का 9 मई की रात को पीएम मोदी को किया गया फोन

इस वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने ट्रंप को क्वाड की अगली बैठक के लिए भारत आने का न्योता भी दिया। ट्रंप ने यह न्योता स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने को लेकर उत्सुक हैं। इसके अतिरिक्त दोनों नेताओं ने इजरायल-ईरान तनाव, रूस-यूक्रेन युद्ध और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर भी विचार साझा किए।

रहा। वैंस ने चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो भारत उससे भी बड़ा और निर्णायक जवाब देगा। और ऐसा ही हुआ, 9–10 मई की रात भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर जबरदस्त जवाब दिया, जिससे पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान पहुंचा और उसे भारत से सैन्य कार्रवाइयों को रोकने का आग्रह करना पड़ा।

इस पूरी कूटनीतिक कवायद में एक और रोचक बात सामने आई कि प्रधानमंत्री मोदी की क्रोएशिया यात्रा को प्राथमिकता देना सिर्फ एक तय कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, बल्कि रणनीतिक रूप से सोचा–समझा निर्णय था। अगर मोदी अमेरिका जाते और उसी दिन व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर भी मौजूद होते, तो यह दृश्य दुनिया को भारत की कमजोरी या कूटनीतिक भ्रम का संकेत दे सकता था।

भारत की यह परिपक्वता बताती है कि अब हमारी विदेश नीति किसी भी अंतरराष्ट्रीय दबाव में नहीं चलती, बल्कि देशहित को सर्वोपरि रखते हुए निर्णय लिए जाते हैं। अमेरिकी मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ट्रंप ने शायद एक "ओवर स्मार्ट" चाल चली थी, एक ओर पाकिस्तान के सेना प्रमुख को बुलाना, और दूसरी ओर मोदी को भी उसी दिन आमंत्रित करना। लेकिन भारत ने समय रहते इस चाल को समझ लिया और इससे खुद को अलग रखा। इस प्रकार की राजनीतिक सतर्कता और परिपक्वता भारत को वैश्विक मंच पर एक ठोस और भरोसेमंद ताकत के रूप में स्थापित करती है।

बातचीत के बाद ट्रंप ने भी इस बात को स्वीकार किया कि भारत की आतंकवाद विरोधी नीति न सिर्फ स्पष्ट है, बल्कि निर्णायक भी है। उन्होंने भारत की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब वह हर आतंकी हरकत का जवाब अपनी शर्तों पर देगा और अंतरराष्ट्रीय समर्थन की प्रतीक्षा नहीं करेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत की विदेश नीति के दो प्रमुख पहलू उजागर किए:

- **आतंकी घटनाओं को लेकर भारत की सख्त और स्पष्ट नीति**
- **अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आत्मनिर्भर और निर्णायक रुख**

ट्रंप के साथ यह बातचीत एक ओर भारत–अमेरिका संबंधों की गहराई को दर्शाती है, तो दूसरी ओर भारत की स्वायत्तता और कूटनीतिक सूझबूझ का प्रमाण भी देती है।

टेलीफोन पर हुई इस बातचीत से यह स्पष्ट हो गया है कि भारत अब किसी की मध्यस्थता या सहमति का मोहताज नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के मामलों में भारत पूरी तरह से अपने निर्णय खुद ले रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में न रुकने का निर्णय एक तरह से राजनीतिक परिपक्वता, रणनीतिक सोच और राष्ट्रीय स्वाभिमान का बेहतरीन उदाहरण है। अंततः यह वार्ता केवल 35 मिनट की एक औपचारिक बातचीत नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश था दुनिया को, पाकिस्तान को, और शायद अमेरिका को भी कि नया भारत अपने हितों के लिए हर मोर्चे पर सतर्क, संप्रभु और संकल्पित है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अमेरिका में न रुकने तक, हर निर्णय में भारत की विदेश नीति की परिपक्वता और रणनीतिक सोच साफ तौर पर दिखाई देती है। यही कारण है कि अब दुनिया भारत की बात सिर्फ सुनती नहीं, उस पर गंभीरता से विचार भी

मोदी का हनुमान

अब खुद बनना चाहता है बिहार का राम

हर पिता की यह ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा उसकी विरासत को आगे बढ़ाए और जब बात राम विलास जैसे करिश्माई नेता की हो, जिन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी खास पहचान बनाई, तो यह जिम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती है। चिराग पासवान यह बात न सिर्फ समझते हैं, बल्कि इसे अपनी राजनीतिक यात्र का मुख्य आधार भी बना चुके हैं।

संजय सक्सेना
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ

बिहार की राजनीति एक बार फिर बदलाव के मुहाने पर खड़ी है और इस बार केंद्र में हैं चिराग पासवान, जो अपने पिता राम विलास पासवान के अधूरे सपनों को पूरा करने की ओर तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हर पिता की यह ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा उसकी विरासत को आगे बढ़ाए और जब बात राम विलास जैसे करिश्माई नेता की हो, जिन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी खास पहचान बनाई, तो यह जिम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती है। चिराग पासवान यह बात न सिर्फ समझते हैं, बल्कि इसे अपनी राजनीतिक यात्रा का मुख्य आधार भी बना चुके हैं। अक्सर वह यह कहते पाए जाते हैं कि वह अपने पिता के दिखाए रास्ते पर चलना चाहते हैं, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट होता जा रहा है कि चिराग की राजनीतिक समझ और महत्वाकांक्षा का दायरा कहीं अधिक व्यापक है। चिराग अब बिहार के राजनीतिक मौसम का अध्ययन करने के साथ–साथ उसकी दिशा बदलने का माद्दा भी रखते हैं।

जब 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में चिराग ने एनडीए के भीतर रहते हुए भी जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह नौजवान नेता इतनी जल्द फिर से भाजपा के साथ खड़ा हो जाएगा। पर आज की तारीख में वह केंद्र सरकार में मंत्री हैं और भाजपा के साथ एक बार फिर मजबूत रिश्तों की बुनियाद पर खड़े हैं। यह वही चिराग हैं जो कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन करते थे और 2005 में उन्होंने मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग कर सनसनी फैला दी थी। लेकिन अब वह भाजपा की विचारधारा के साथ कदमताल कर रहे हैं। यह एक चौंकाने वाला लेकिन रणनीतिक बदलाव है। यह बदलाव सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं, भविष्य के लिए एक रोडमैप है जिसमें चिराग खुद को बिहार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं।

हालांकि चिराग पासवान ने अभी तक सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं जताई है, लेकिन उनकी पार्टी के नेता लगातार यह मांग कर रहे हैं और चिराग खुद भी इन अटकलों को खारिज करने के बजाय हवा देते नजर आते हैं। बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार अब उस ऊर्जा और प्रभाव के साथ शासन नहीं कर पा रहे जो कभी उनकी पहचान थी। उनके बार–बार के पाला बदलने और अप्रत्याशित फैसलों ने उनकी साख को नुकसान पहुंचाया है। भाजपा के लिए अब यह जरूरी हो गया है कि वह एक नया चेहरा सामने लाए जो बिहार में न सिर्फ गठबंधन का नेतृत्व कर सके, बल्कि जनता में भी उसे स्वीकार्यता मिले। चिराग पासवान एकमात्र विकल्प की तरह सामने आते हैं जो तेजस्वी यादव को चुनौती दे सकते हैं और नीतीश कुमार का स्थान ले सकते हैं।

तेजस्वी यादव फिलहाल महागठबंधन के सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं। उनका युवा चेहरा, सामाजिक न्याय की राजनीति और पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन उन्हें मजबूत बनाता है। तेजस्वी की लोकप्रियता अगर 36.9: है तो चिराग भी 10.6: पर हैं, जो कि बिना किसी औपचारिक मुख्यमंत्री पद के दावेदारी के ये आंकड़ा काफी मजबूत माना जा सकता है। नीतीश कुमार खुद अब 18.4: पर हैं, जो यह दिखाता है कि उनकी लोकप्रियता में तेजी से गिरावट आई है। चिराग और तेजस्वी दोनों हमउम्र हैं, दोनों युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं और दोनों ही अगड़े–पिछड़े वर्गों में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चिराग को शबिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्टश अभियान से जो अतिरिक्त बढ़त मिली है, वह उन्हें एक अलग पहचान देती है।

चिराग पासवान की राजनीतिक समझ इस बात से भी जाहिर होती है कि वह गठबंधन की राजनीति को बारीकी से समझते हैं। वह जानते हैं कि भाजपा को बिहार में समर्थन की जरूरत है, और वह यह भी जानते हैं कि भाजपा को नीतीश कुमार जैसे नेता से धीरे–धीरे पीछा छुड़ाना है। ठीक वैसे ही जैसे उसने असम में हिमंत बिस्वा सरमा और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को अवसर दिया। चिराग को इस बात की भी पूरी समझ है कि भाजपा तब तक नीतीश के साथ रहेगी जब तक उसे कोई नया विकल्प नहीं मिल जाता, और वह खुद को उसी विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यह रणनीति है, जो समय आने पर चिराग को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा सकती है।

चिराग पासवान अब सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि संभावनाओं के प्रतीक बन चुके हैं। वह रिजर्व सीट से नहीं, बल्कि सामान्य विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। उनका आत्मविश्वास है, जो उन्हें बिहार के राजनीतिक केंद्र में खड़ा करता है। केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी अगर वह विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो यह संकेत है कि वे दिल्ली से पटना की ओर एक नई राजनीतिक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। यह यात्रा सिर्फ उनके लिए नहीं, पासवान समुदाय व भाजपा के लिए भी नए राजनीतिक समीकरण रच सकती है।

भाजपा के भीतर भी एक लंबे समय से नीतीश कुमार के विकल्प की तलाश चल रही है। सम्राट चौधरी जैसे नेता भी सामने लाए गए लेकिन वे नीतीश की लव–कुश सोशल इंजीनियरिंग को चुनौती देने में सक्षम नहीं रहे। ऐसे में चिराग पासवान न सिर्फ पासवान समुदाय के वोटों को साध सकते हैं, बल्कि पिछड़ा और दलित वर्ग में भी एक नई उम्मीद जगा सकते हैं। राष्ट्रीय पहचान, युवा चेहरा और भाजपा के साथ मजबूत रिश्ते उन्हें उस मुकाम पर ले जा सकते हैं जहां से वे मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में खड़े हो सकते हैं।

अब सवाल यह उठता है कि अगर भाजपा चिराग को मुख्यमंत्री पद देने के बदले उनकी पार्टी का विलय चाहती है तो क्या चिराग इसके लिए तैयार होंगे? राजनीति में ऐसे विलय पहले भी हुए हैं और अगर चिराग के सामने मुख्यमंत्री बनने का मौका हो, तो यह त्याग उन्हें मंजूर भी हो सकता है। वैसे भी, चिराग पहले ही खुद को मोदी का श्हनुमानश कह चुके हैं, और उनके साथ अपनी निष्ठा को बार–बार साबित भी कर चुके हैं। इसलिए भाजपा अगर सही समय पर यह प्रस्ताव लेकर आती है, तो चिराग भी पीछे नहीं हटेंगे।

हालांकि भाजपा के भीतर भी यह चिंता हो सकती है कि चिराग जैसे नेता को आगे करने से बाकी सहयोगी दलों को क्या संदेश जाएगा। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि बिहार में भाजपा को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो युवाओं, दलितों और मध्यम वर्ग को एक साथ जोड़े। और इस भूमिका में चिराग पासवान एकमात्र स्वाभाविक नेता के रूप में सामने आते हैं। अगर भाजपा नहीं भी तैयार होती है, तो यह भी संभव है कि प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार, जो अक्सर चिराग की तारीफ करते हैं, भविष्य में उनके समर्थन में एक नया मोर्चा तैयार करें। यह चिराग पासवान के लिए एक निर्णायक क्षण है। अगर वे सही रणनीति अपनाते हैं, भाजपा के साथ संतुलन साधते हैं और जनता में अपनी मजबूत छवि गढ़ने में कामयाब होते हैं, तो वह दिन दूर नहीं जब बिहार की सत्ता का केंद्र चिराग बन जाएं। यह सपना सिर्फ चिराग का नहीं, राम विलास

सरकार ने ऑनलाइन स्कैम पर कसा शिकंजा-चार मोर्चों पर लिया एक्शन

ऑनलाइन ठगी पर सख्ती: धार्मिक यात्राओं, होटल और कैब बुकिंग के नाम पर हो रहे फ्रॉड पर केंद्र सरकार की कड़ी कार्रवाई

देशभर में केदारनाथ, वैष्णो देवी जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा, होटल व कैब बुकिंग और हेलीकॉप्टर सेवा के नाम पर बढ़ रही ऑनलाइन धोखाधड़ी पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है।

गृह मंत्रालय ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के माध्यम से चार स्तरों पर कार्रवाई तेज कर दी है। फर्जी वेबसाइटें, जो अधिकृत साइटों से मिलते–जुलते नाम और डिजाइन रखती हैं, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया और सर्च इंजन पर पेड विज्ञापनों के जरिये लोगों को झांसे में ले रही हैं। जैसे ही लोग भुगतान करते हैं, संपर्क नंबर बंद या 'आउट ऑफ रीच' हो जाते हैं।

फर्जी लिंक और विज्ञपन होंगे पहचान के दायरे में

सरकार ने गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर "स्कैम सिग्नल एक्सचेंज" की प्रक्रिया तेज की है ताकि फर्जी विज्ञापनों और वेबसाइटों की पहचान कर उन्हें रोका जा सके। धोखाधड़ी के अधिक मामले वाले क्षेत्रों में प्रवर्तन एजेंसियों की निगरानी बढ़ा दी गई है और नकली वेबसाइटों व पेमेंट गेटवे को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

चार स्तरों पर हो रही कार्रवाई

स्कैम सिग्नल एक्सचेंजः गूगल, वॉट्सऐप, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स से नियमित रूप से धोखाधड़ी के संकेत साझा कर कार्रवाई।

प्रवर्तनः संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां निगरानी और कानूनी कार्रवाई।

साइबर पेट्रोलिंगः फर्जी वेबसाइटों और विज्ञापनों की पहचान कर उन्हें हटाना।

रिपोर्टिंग सुविधाः साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (बलइमतबतपउम.हवअ.पद) और हेल्पलाइन नंबर 1930 पर त्वरित शिकायत और कार्रवाई की व्यवस्था।

ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए अपनाएं ये 5 जरूरी उपाय

केवल आधिकारिक वेबसाइट या ऐप का उपयोग करेंरू बुकिंग या खरीदारी करते समय केवल प्रमाणिक और सरकारीध्मान्य वेबसाइट्स जैसे *-gov-in* या कंपनी के असली डोमेन का उपयोग करें।

अज्ञात लिंक और कॉल से बचें: ईमेल SMS या सोशल मीडिया पर आए अनजान लिंक या QR कोड पर क्लिक न करें।

सोशल मीडिया विज्ञापनों से सतर्क रहें: आकर्षक ऑफर्स वाले फर्जी विज्ञापनों से सावधान रहें और बिना सत्यापन के भुगतान न करें।

साइबर सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करें: मोबाइल और कंप्यूटर में एंटी–वायरस, फायरवॉल और सुरक्षित ब्राउजिंग एक्सटेंशन लगाएं।

संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करें: किसी स्कैम का शिकार होने पर www-cybercrime-gov-in पर शिकायत दर्ज करें या 1930 पर कॉल करें।

यूपी: योगी सरकार ने पुलिस बल में किए ऐतिहासिक बदलाव

प्रदेश में आठ वर्षों में 2-16 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती

पिछले आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश की कानून–व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने सुरक्षा ढांचे को मजबूत करते हुए पुलिस बल के पुनर्गठन में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं।

रिकॉर्ड स्तर पर भर्ती

2017 से अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस में 2.16 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई है, जिनमें 27,178 महिलाएं शामिल हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और तकनीकी माध्यमों से की गई, जिससे युवाओं का सरकारी व्यवस्था पर भरोसा और भी मजबूत हुआ है।

खेल प्रतिभाओं को भी मिला अवसर

राज्य सरकार ने खेल प्रतिभा को भी समान अवसर प्रदान करते हुए 500 खिलाड़ियों को पुलिस बल में शामिल किया, जिससे बल की क्षमता और प्रेरणा दोनों में इजाफा हुआ है।

सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता की मिसाल

योगी सरकार के दौरान 8.5 लाख युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सरकारी नौकरियों में नियुक्ति मिली, वहीं संविदा के तहत 3.75 लाख पद भरे गए। निजी क्षेत्र और एमएसएमई के माध्यम से दो करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने से अपराध दर में भी गिरावट आई है।

पुलिस बल की वर्तमान स्थिति

वर्तमान में यूपी पुलिस में 4.21 लाख से अधिक कर्मी कार्यरत हैं, जो किसी भी राज्य के लिहाज से बड़ी संख्या है, और यह राज्य की आंतरिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने का संकेत है।

नए आपराधिक कानूनों की प्रभावी क्रियान्विति

- भारतीय न्याय संहिता (BNS)
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BEB)

यूपी पुलिस ने देश के तीन नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू किया है, जिससे अपराधियों के विरुद्ध तेज, तकनीकी और पारदर्शी कार्रवाई संभव हो सकी है।

फॉरेंसिक और विधि विज्ञान का विकास

अपराधों की वैज्ञानिक जांच के लिए लखनऊ में फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई। साथ ही 2017 के बाद से 8 नई फॉरेंसिक लैब्स शुरू की गईं और 6 निर्माणाधीन हैं।

विशेष सुरक्षा बलों को मजबूती

- एटीएस
- एसटीएफ
- एसडीआरएफ
- एसएसएफ

राज्य में विभिन्न विशेष सुरक्षा इकाइयों को सशक्त किया गया है, जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में विशेष भूमिका निभा रही हैं।

हेल्पलाइन व्यवस्था का आधुनिकीकरण

- जनसहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 112
- महिला हेल्पलाइन नंबर 1090
- चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 बाल सहायता को अत्याधुनिक तकनीक और प्रशिक्षित स्टाफ से सुदृढ़ किया गया है।

महिला सुरक्षा के लिए ठोस कदम

- लखनऊ, बदायूं, गोरखपुर में वीरांगना पीएसी बटालियनों की स्थापना
- 1,595 महिला हेल्प डेस्क
- 75 महिला थाने
- 78 महिला परामर्श केंद्र
- 346 महिला पीआरवी
- 10,378 महिला बीट का आवंटन

इन कदमों से महिलाओं में सुरक्षा की भावना और समाज में पुलिस की सकारात्मक छवि दोनों को बल मिला है।

बुनियादी ढांचे का विस्तार

- 131 नए थाने
- 82 फायर स्टेशन
- 75 साइबर क्राइम थाना
- 10 सतर्कता अधिष्ठान
- 6 एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स थाने

यूपी पुलिस ने योगी सरकार के कार्यकाल में न केवल अपनी संख्या बढ़ाई है, बल्कि संवेदनशीलता, तकनीकी दक्षता और सेवा भावना में भी खुद को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया है। अब यूपी, सुरक्षा के क्षेत्र में दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणास्त्रोत बनता जा रहा है।

इस युद्ध का भविष्य अनिश्चित है, इसके परिणाम पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगे

दोनों देशों के बीच छिड़ा युद्ध, जो पहले केवल छद्म युद्ध या प्रश्वक्सी संघर्षों तक सीमित था,उसके हालात काफी बदल चुके हैं और यह अब सैन्य टकराव का रूप ले चुका है, दोनों देश एक-दूसरे को खत्म कर देने की धमकी दे रहे हैं

संजय सक्सेना
वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ

ईरान–इजरायल युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव और संघर्ष मध्य पूर्व की भू–राजनीति का एक गंभीर और दीर्घकालिक मुद्दा बनता जा रहा है, जो 2025 में और अधिक गहरा हो गया है। दोनों देशों के बीच छिड़ा युद्ध, जो पहले केवल छद्म युद्ध या प्रॉक्सी संघर्षों तक सीमित था,उसके हालात काफी बदल चुके हैं और यह अब सैन्य टकराव का रूप ले चुका है, दोनों देश एक–दूसरे को खत्म कर देने की धमकी दे रहे हैं। इन देशों का युद्ध क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत कर रहा है। वहीं अन्य देश भी इस युद्ध को खत्म कराने की कोशिश करने की बजाये दोनों देश के बीच एक पक्ष बनते जा रहे हैं। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन जैसे तमाम देश अपने देश के हितों को ध्यान में रखकर फैसला ले रहे हैं। सही–गलत का कोई पैमाना ही नहीं रहा है। दोनों देश एक–दूसरे पर घातक हथियारों से हमला कर रहे हैं।

गौरतलब यह है कि ईरान और इजरायल के बीच शत्रुता की जड़ें 1979 की ईरानी क्रांति में निहित हैं, जब आयतुल्लाह खोमैनी के नेतृत्व में इस्लामी गणतंत्र की स्थापना हुई। इस क्रांति ने न केवल ईरान की विदेश नीति को पुनर्परिभाषित किया, बल्कि इजरायल को एक प्रमुख शत्रु के रूप में चिह्नित किया। ईरान ने इजरायल को अवैध जायोनी शासन के रूप में देखा और फिलिस्तीनी मुद्दे को अपने क्षेत्रीय प्रभाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। दूसरी ओर, इजरायल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्र में इसके प्रभाव, विशेष रूप से हिजबुल्लाह और हमास जैसे समूहों के समर्थन को, अपने अस्तित्व के लिए खतरे के रूप में देखा। यह वैचारिक और रणनीतिक टकराव दशकों तक प्रॉक्सी युद्धों के रूप में प्रकट हुआ, विशेष रूप से सीरिया, लेबनान और यमन में।

इस साल के मध्य में यह तनाव प्रत्यक्ष सैन्य टकराव में बदल गया है। जून 2024 में इजरायल द्वारा ईरान के महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले और जून 2025 में एक ईरानी टेलीविजन भवन पर हमले ने इस संघर्ष को नए स्तर पर पहुंचा दिया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में मिसाइल हमले किए, ईरान ने इजरायल पर क्लस्टर मिसाइल से भी अटैक किया। हालांकि इजरायल का आयरन डोम और अन्य रक्षा तंत्र इनमें से अधिकांश हमलों को नाकाम करने में सफल रहे, लेकिन पूरी तरह से वह इसे नहीं रोक पाये। इन हमलों ने दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं और कमजोरियों को

उजागर किया। इजरायल की उन्नत तकनीक और सटीक हमले करने की क्षमता ने ईरान के हवाई रक्षा तंत्र की अपर्याप्तता को सामने ला दिया, जबकि ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों ने इजरायल के लिए एक गंभीर खतरा प्रस्तुत किया।

दोनों देश के बीच छिड़े इस संघर्ष का एक प्रमुख कारक ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी है। इजरायल बार–बार दावा कर रहा है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में अग्रसर है, जो उसके अस्तित्व के लिये खतरा है। 2015 के परमाणु समझौते के पतन के बाद, विशेष रूप से 2018 में अमेरिका के इससे बाहर निकलने के बाद, ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को तेज कर दिया।

2025 तक, कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दहलीज पर पहुंच चुका है, हालांकि यह दावा विवादास्पद और असत्यापित है। इजरायल ने इस खतरे को कम करने के लिए साइबर हमले (जैसे स्टक्सनेट) और लक्षित हत्याओं का सहारा लिया, जिसने ईरान को और अधिक आक्रामक रुख अपनाने के लिए प्रेरित किया।

उधर, क्षेत्रीय गठबंधन और वैश्विक शक्तियों की भूमिका इस संघर्ष को और जटिल बनाती है। इजरायल को अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों का समर्थन प्राप्त है, जो अब्राहम समझौते के बाद और मजबूत हुआ है। दूसरी ओर, ईरान ने रूस, चीन और अपने प्रॉक्सी समूहों जैसे हिज्बुल्लाह और हूती विद्रोहियों के साथ गठबंधन बनाए रखा है। हालांकि, रूस और चीन की प्रत्यक्ष सैन्य सहायता सीमित रही है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा है और चीन क्षेत्रीय संघर्ष में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से बचता है। भारत जैसे देश, जो दोनों देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध रखते हैं, तटस्थ रुख अपनाए हुए हैं, जो उनकी ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता की चिंताओं को दर्शाता है।

ईरान के परमाणु बम से इत्तर बात कि जाये तो आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भी इस युद्ध का एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। ईरान, पहले से ही प्रतिबंधों और आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इजरायल के हमलों से और कमजोर हुआ है। ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले ने तेल उत्पादन और निर्यात को प्रभावित किया, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा। दूसरी ओर, इजरायल की अर्थव्यवस्था, जो तकनीक और नवाचार पर आधारित है, इस युद्ध के बावजूद अपेक्षाकृत स्थिर रही, हालांकि निरंतर युद्ध ने सामाजिक तनाव को बढ़ाया है। दोनों देशों में जनता युद्ध की थकान और अनिश्चितता से जूझ रही है, जिसने आंतरिक असंतोष को जन्म दिया है।

इस संघर्ष के संभावित परिणाम कई दिशाओं में जा सकते हैं। सबसे खतरनाक परिदृश्य एक पूर्ण युद्ध है, जिसमें परमाणु हथियारों का उपयोग शामिल हो सकता है। कुछ स्रोतों के अनुसार, अमेरिका में 2025 के अंत तक परमाणु हमले की संभावना पर सट्टेबाजी हो रही है, जो इस खतरे की गंभीरता को दर्शाता है। दूसरी ओर, कूटनीतिक हस्तक्षेप, विशेष रूप से तटस्थ मध्यस्थों जैसे संयुक्त राष्ट्र या क्षेत्रीय शक्तियों के माध्यम से, युद्ध को सीमित कर सकता है। हालांकि, दोनों देशों के नेतृत्व की कठोर रवैया और क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता इसे मुश्किल बनाती है।

वैश्विक प्रभाव की दृष्टि से, यह युद्ध तेल की कीमतों में उछाल, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और शरणार्थी संकट को जन्म दे सकता है। मध्य पूर्व पहले से ही अस्थिर है, और इस युद्ध ने सीरिया, लेबनान और यमन जैसे देशों में प्रॉक्सी संघर्षों को और भड़का दिया है। इसके अलावा, यह युद्ध वैश्विक शक्तियों के बीच ध्रुवीकरण को बढ़ा सकता है, जिसमें अमेरिका और उसके सहयोगी एक तरफ और रूस–चीन गठबंधन दूसरी तरफ खड़े हों।

कुल मिलाकर ईरान–इजरायल युद्ध 2025 में एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, जिसमें ऐतिहासिक शत्रुता, परमाणु महत्वाकांक्षाएं, क्षेत्रीय गठबंधन और वैश्विक हस्तक्षेप शामिल हैं। यह संघर्ष न केवल मध्य पूर्व, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती है। इसके समाधान के लिए कूटनीति, संयम और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में यह एक दूर की कौड़ी प्रतीत होता है। इस युद्ध का भविष्य अनिश्चित है, और इसके परिणाम न केवल दोनों देशों, बल्कि पूरे विश्व के लिए निर्णायक होंगे।

पेशाब से मीठी या फल जैसी गंध को न करें नजरअंदाज' हो सकता है ब्लड शुगर बढ़ने का संकेत

क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पेशाब से मीठी या फल जैसी गंध आ रही है? यदि हां, तो इसे हल्के में न लें। यह कोई सामान्य बात नहीं, बल्कि शरीर का संकेत हो सकता है कि ब्लड शुगर असामान्य रूप से बढ़ रहा हैकृविशेषकर यदि आप प्री–डायबेटिक हैं या डायबिटीज के खतरे के दायरे में आते हैं।

क्यों आती है पेशाब से मीठी गंध?

जब शरीर में ग्लूकोज का स्तर बहुत अधिक हो जाता है, तो वह उसे पेशाब के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसी वजह से पेशाब से मीठी या फ्रूटी गंध आने लगती है। इसके पीछे दो मुख्य कारण हो सकते हैं:

उच्च ब्लड शुगर:

शरीर अतिरिक्त ग्लूकोज को यूरिन के माध्यम से बाहर निकालता है, जिससे गंध आने लगती है।

कीटोएसिडोसिस:

जब शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज नहीं मिलती, तो वह फैट जलाकर कीटोन्स बनाता है। ये कीटोन्स सांस और पेशाब में मीठी–फल जैसी गंध ला सकते हैं। यह स्थिति गंभीर है और इसे डायबीटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं।

इन लक्षणों के साथ पेशाब में गंध हो तो तुरंत सतर्क हो जाएं:

- अत्यधिक प्यास लगना
- बार–बार पेशाब आना
- असामान्य थकान या कमजोरी
- अचानक वजन घटना
- धुंधली दृष्टि
- सांसों में फल जैसी गंध

यदि इनमें से कई लक्षण एक साथ दिखें, तो तुरंत ब्लड शुगर की जांच करवाएं।

अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 100-125 mg/dL है:

इसका मतलब है कि आप प्री–डायबेटिक जोन में हैं। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में बड़े बदलाव करें:

- रोज कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें
- मीठा और प्रोसेस्ड फूड कम करें
- तनाव कम करें और नींद पूरी लें
- हर 3 महीने में HbA1c टेस्ट कराएं

आपको बता दें मीठी गंध वाली पेशाब कोई मामूली बात नहीं है। यह शरीर का अलार्म है कि कुछ गड़बड़ है। यदि ऐसे संकेत नजर आएं तो देरी न करें, ब्लड शुगर की जांच करवाएं और जरूरत हो तो डॉक्टर से मिलें। समय रहते सावधानी बरतकर आप बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं।

संभावित कारण और उपाय

हाई ब्लड शुगर	हाई ब्लड शुगर	हाई ब्लड शुगर
हाई ब्लड शुगर	पेशाब में मीठी-फल जैसी गंध	तुरंत ब्लड शुगर टेस्ट करवाएं
कीटोएसिडोसिस	उल्टी, सांस में गंध, थकान	आपातकालीन इलाज लें
यूटीआई (मूत्र संक्रमण)	पेशाब में दर्द, खून	डश्वक्टर से संपर्क करें
डिहाइड्रेशन	गाढ़ी पेशाब, कम मात्र	पानी की मात्र बढ़ाएं

मेरा पन्ना

अस्तित्व

कवयित्री प्रज्ञा श्रीवास्तव प्रज्ञाञ्जलि

याद रखो तुम
धरती ने आकाश से कहा
दूर रहकर भी दूर
नहीं हैं हम
अस्तित्व ना मेरा कम है ना तुम्हारा
नदियाँ आसमान पर नहीं बहती
और पंछी धरती पर नहीं उड़ते
बोझ मुझ पर ज्यादा है
कहते हो ना तुम
जानती हूँ हर बार
जीत हासिल हुई है तुम्हें ये कहकर
बड़े दिलवाले बन जाते हो
उड़ते हुए परिंदे,
तैरते बादल
मंद-मंद बहती हवा
कितनी अच्छी लगती है
हल्की-हल्की सी
और मैं लदी हूँ बोझ से
कितना दर्द, कितनी पीड़ा
कोई नहीं मेरा अपना
छिन रही है मेरी हरियाली
छिन्न-भिन्न सब कुछ
बलि चढ रहा है स्वार्थ की
और मेरे दर्द देखकर
तुम्हारे दिल में छेद हो गया है
कैसे समझाऊँ
कितनी चिंता है मुझे तुम्हारी
अपना ख्याल रखो
मुझे तो सहना है....

RNI No. UTTHIN/2021/80704

प्रकाशन की तिथि- प्रत्येक माह की 7 तारीख
प्रेषण दिनांक- प्रत्येक माह की 10 तारीख

विभिन्न विषयों पर आधारित हिन्दी मासिक पत्रिका

तीर निशाने पर

विशिखा

राजस्थान की राजधानी जयपुर एवं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बाद विशिखा

अब शीघ्र ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी प्रकाशित...

मुख्यालय : विशिखा मीडिया 191/56, सेक्टर-19, प्रताप नगर, सांगानेर
जयपुर-302033 (राज.)
Contact us: +911413562171, 9587455444
E-mail: vishikhamedia@gmail.com | Website: www.vishikhamedia.in
vishikhamedia/ _vishikhamedia/ vishikhamedia